कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

यूपीए–2 के चार वर्ष

यूपीए सरकार का गत चार साल का सफर काफी निराशाजनक रहा..... 6
समाचार–पत्रों ने कहा..... 8

लेख

क्या उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई का महत्व घटाया है अथवा उसे मजबूत किया है
– **अरुण जेटली**..... 12
कांग्रेस के खाली ढोल की खुली पोल
–**अम्बा चरण वशिष्ठ**..... 14
विश्वास खो चुके हैं प्रधानमंत्री
–**बलबीर पुंज**..... 18
मात्र राजनयिक सम्बंध ही नहीं, भारत–चीन के बीच दृढ़ विश्वास बने
–**राम प्रसाद त्रिपाठी**..... 20

साक्षात्कार

मंगल पाण्डे : बिहार भाजपा अध्यक्ष..... 23

अन्य

भाजपा प्रदेश प्रभारियों एवं प्रकोष्ठ संयोजकों की घोषणा..... 16

प्रादेशिक गतिविधियां

मध्य प्रदेश..... 22
छत्तीसगढ़ विकास यात्रा..... 25
केरल..... 26
झारखण्ड, बिहार..... 27
हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड..... 28
राजस्थान..... 29

मुख पृष्ठ : *यूपीए–2 के चार वर्ष पर संयुक्त प्रेस वार्ता*

ऐतिहासिक चित्र

श्री गुरुजी एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी दीनदयाल शोध संस्थान, दिल्ली के स्थापना समारोह में पूजा करते हुए।

बोध कथा

श्रीराम जी की अनूठी विनम्रता

लंका में रावण, उसके पुत्रों तथा राक्षस सेना का संहार करने के बाद भगवान श्रीराम ने विभीषण को यह आदेश दिया कि सीता जी को ससम्मान पुष्प वाटिका से ले आओ। विभीषण ने लंका में उपलब्ध सर्वोत्कृष्ट पालकी मंगवाई। राक्षसियों ने सीता जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, उत्तम आभूषणों से शृंगार किया और उन्हें ससम्मान पालकी में बिठाया गया।

विभीषण के सेवक राक्षस पालकी को उठाकर श्रीराम के शिविर की ओर चल दिए। पालकी में रेशमी वस्त्रों के परदे लगे थे। जब सीताजी को लिए पालकी हनुमान जी की वानर सेना के निकट पहुंची, तो वानर सैनिक उनके दर्शन के लिए पालकी के चारों ओर आने लगे। कुछ वानरों ने पालकी के रेशमी परदों को हटाने का प्रयास किया। पहरेदारों ने अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उन्हें दूर जाने तथा बाद में दर्शन करने के लिए कहा।

श्रीराम यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने विभीषण से कहा, सीता जी की पालकी को परदे से नहीं घेरा जाना चाहिए था। हनुमान और सुग्रीव की अनुयायी इस वानर सेना ने उनकी मुक्ति के लिए अनेक कष्ट उठाए। वे उनमें मां की श्रद्धा भावना रखकर दर्शन को उत्सुक हैं। सीता जी को पैदल चलकर आना चाहिए था।

श्रीराम की बात सुनकर सभी उनकी इस विनम्रता के समक्ष नतमस्तक हो उठे।

प्रस्तुति : शिव कुमार गोयल

(अमर उजाला से साभार)

व्यंग्य चित्र

यूपीए के ये चार वर्ष...!

समाधकीय

अंधकार के चार वर्ष। कालिख भरे चार वर्ष। घोटालों के चार वर्ष। साख गिरने के चार वर्ष। सीमा, सरहद और सेना की असुरक्षा के चार वर्ष। आर्थिक खोखलेपन के चार वर्ष। महंगाई रूपी मौत के चार वर्ष। असफल विदेश नीति के चार वर्ष। चौपट कानून-व्यवस्था के चार वर्ष। जान-माल की असुरक्षा के चार वर्ष। डॉ. मनमोहन सिंह+सोनिया गांधी+राहुल गांधी+मंत्रिमंडल के सदस्य+गठबंधन के नेतागण के मौज-मस्ती के चार वर्ष। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के डूबते जहाज के चार वर्ष। संघीय ढांचा को चरमराने वाले चार वर्ष। विरोधी दलों के नेताओं को कुचलने के चार वर्ष। संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त करने के चार वर्ष। लोकतंत्र के चारों पायों को तोड़ने के चार वर्ष। मनरेगा के नाम पर मजदूरों को लूटने के चार वर्ष। सब्सिडी के नाम पर किसानों को ठगने के चार वर्ष। खस्ताहाल शिक्षा व्यवस्था के चार वर्ष। अबला-असहाय महिलाओं की असुरक्षा के चार वर्ष। न्याय के नाम पर न्यायमंदिरों को प्रभावित करने के चार वर्ष। स्वायत्तशासी संस्थाओं को सरकारी दांतों से दबोचने के चार वर्ष। भूखी-गरीब जनता को नग्न करने के चार वर्ष। केरोसिन और पेट्रोल के दाम हर महीने बढ़ाकर खेत-खलिहान को चौपट करने के चार वर्ष। एफडीआई के नाम पर स्वदेशी स्वाभिमान को चोट देने के चार वर्ष। रेलवे का किराया बढ़ाने के चार वर्ष। विकास के नाम पर विनाश परोसने के चार वर्ष। पर्यावरण के नाम पर प्रदूषण फैलाने के चार वर्ष। निवेश के नाम पर भारतीय उद्योग चौपट करने के चार वर्ष। यूपीए के गठबंधन के टूटने के चार वर्ष। बसपा और सपा की अवसरवादी राजनीति के चार वर्ष। डॉ. मनमोहन सिंह की कठपुतली शासन के चार वर्ष। सोनियाजी की दादागिरी के चार वर्ष। परिवार द्वारा भ्रष्टाचार के चार वर्ष। सास, दामाद और बेटे की काली करतूतों के चार वर्ष। महात्मा गांधी की आड़ में गांधी उपनाम के दुरूपयोग के चार वर्ष। कांग्रेस पर एकाधिकार के चार वर्ष। उत्तर प्रदेश, बिहार से सफाए के चार वर्ष। राहुल को महामंत्री से उपाध्यक्ष बनाने में कांग्रेस के चौपट हुए चार वर्ष। शायद इन उपलब्धियों पर कांग्रेस नाज़ करे, पर इन करतूतों से हर भारतीयों का सिर शर्म से झुक गया है।

यूपीए शासन के पिछले चार वर्षो में तिरंगे का सम्मान तार-तार हुआ है। सेना की वर्दियों पर प्रश्नचिह्न लगे हैं। जहां सेना की स्थिरता को चोट पहुंची है, वहीं सरहद पर सेना के सिर की कीमत का बदला नहीं लिया गया। सीएजी की रिपोर्ट पर कार्रवाई के बजाए उलटे सीएजी को कठघरे में लाने की कोशिश की। सूखे पत्तों की तरह गिरे केंद्रीय मंत्रीगण। असंवैधानिक रूप से चल रही सरकार का नाम है यूपीए। संसद में संख्या नहीं, सड़क पर आवाज नहीं और प्रधानमंत्री मौन! ये कैसी विडंबना है यूपीए की? संसद में बहस से भागती, सड़क के संघर्ष का जवाब नहीं देती, संघीय ढांचे में विश्वास नहीं रखती, देश को निजी जागीर समझकर चलाने वाली यूपीए सरकार के दिन लद गए हैं। परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा देश मानसिक व आर्थिक रूप से त्रस्त हो चुका है। वह उस तारीख की बाट जोह रहा है, जिस दिन लोकतांत्रिक उत्सव हो, चुनाव की तिथि तय हो और परिवर्तन की मानसिकता को देशवासी परिणाम के द्वार तक पहुंचा पाएं। ''लाख-छुपाओ, छुप न सकेगा, दाग है इतना गहरा-दिल की बात बता देता है, असली-नकली चेहरा।'' यूपीए के चेहरे पर लटका हुआ नकाब उतरने में चंद महीने रह गए। कांग्रेसनीत यूपीए चाहे जो करे सरकार से हटना उसकी नियति है। जनता मूड बना चुकी है। अविश्वास की गहरी खाई में उतर चुकी यूपीए द्वारा विश्वास जीतने के नाटक जनता पसंद नहीं करेगी। सोनियाजी और राहुलजी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव सबक सिखानेवाला होगा। तब चुनाव परिणाम के बाद इतिहास लिखने वाले लिखेंगे कि एक विदेशी ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और दूसरे विदेशी सोनिया गांधी ने कांग्रेस को परिवारवाद में बदलकर समाप्त करने की दिशा में तेजी से पहल प्रारंभ की। ■

यूपीए सरकार का गत चार साल का सफर काफी निराशाजनक रहा : भाजपा

यूपीए-2 के चार साल पूरे होने पर 22 मई 2013 को नई दिल्ली भाजपा मुख्यालय में लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज एवं राज्यसभा में विपक्ष नेता श्री अरुण जेटली ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में केंद्र सरकार पर जमकर सवाल उठाए। भाजपा नेता ने कहा कि यूपीए को चार साल पूरे करने का जश्न मनाने का हक नहीं है। उसे तो देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। हम यहां उनके प्रेस वक्तव्य का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:

यूपीए-2 सत्ता में अपने चार वर्ष पूरे कर चुकी है। सामान्य तौर पर किसी भी वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया जाता है लेकिन यूपीए-2 की वर्षगांठ निराशा, हताशा और नकारात्मकता से भरे माहौल में मनाई जा रही है। इससे पहले देश में किसी सरकार के खिलाफ निराशा से भरा अविश्वास का ऐसा माहौल कभी नही रहा जैसा कि आज है।

इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने सत्ता में चार साल पूरे कर लिये हैं लेकिन इतिहास में यूपीए सरकार को इसलिए याद नहीं किया जायेगा कि उसने कितने साल राज किए। बल्कि यूपीए ने देश को जो नुकसान पहुंचाया है उसके कारण बहुत कठोरता से उसका आकलन किया जाएगा क्योंकि लंबे समय तक राज करने की बजाय कोई अपनी क्या छाप छोड़कर जाता है, वहीं आगे के लिये मायने रखता है।

नेतृत्व

यूपीए के नेतृत्व का मॉडल बुनियादी रूप से त्रुटिपूर्ण रहा है। सत्ता का अधिकार प्रधानमंत्री के पास नहीं है। यह अधिकार संविधानेतर लोगों के हाथों में है जिसके कारण सरकार निर्णय नहीं ले पाती है। कोई भी नीतिगत निर्णय हो, यूपीए की अध्यक्ष लेती हैं न कि प्रधानमंत्री। भविष्य के लिये भी पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के वारिस पर नजरें टिकाये हुए हैं न कि प्रधानमंत्री के लिये। प्रधानमंत्री कार्यालय का महत्व खत्म कर दिया गया है। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अनिर्णय, असमर्थता और चुप्पी का पर्याय बन चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की ऐसी गति नहीं हुई थी, जिसे लेकर ताने कसे जा रहे हों, छींटाकशी हो रही हो और उपहास उड़ाया जा रहा हो।

अर्थव्यवस्था

यूपीए को 2004 में, विरासत में, भरी-पूरी अर्थव्यवस्था मिली थी। यूपीए के शुरूआती वर्षों में पिछली नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था में प्रगति दिखाई दी। आर्थिक नीति के लिए बनी ''ड्रीम टीम''बहुत जल्द ही ''असहाय मूकदर्शक'' बनकर रह गई और भारतीय अर्थव्यवस्था को जैसे लकवा मार गया। यूपीए के शासन में तेजी से महंगाई बढ़ी, जिससे आम आदमी का जीना मुहाल हो गया। देश में निवेश का माहौल गड़बड़ा गया। जिस भारतीय अर्थव्यवस्था को बाकी दुनिया के लिये निवेश का अवसर माना जा रहा था, उसने अपना आकर्षण खो दिया। घरेलू और विदेशी निवेश कम होने लगा। देश में निवेश का माहौल पूरी तरह उलटने लगा। भारतीय उद्योगों को दूसरे देश निवेश के लिये बेहतर लगने लगे। रोजगार में वृद्धि की रफ्तार थम गई। विकास दर पांच फीसदी से नीचे चली गई और रोजगार सृजन को करारा झटका लगा।

दूरसंचार, बिजली, राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, बंदरगाहों के निरंतर विकास को गहरा झटका लगा। रुपया कमजोर हो गया। खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने के सरकार के फैसले से घरेलू खुदरा व्यापार, उत्पादन और उपभोक्ता दोनों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने ऐसे कोई सुधार के कदम नही उठाये जिससे कि भारत कम लागत वाली वस्तुओं के निर्माण का केन्द्र बन सके। कृषि क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ। भारतीय किसान भारी कर्ज में डूबता चला गया। सिंचाई सुविधाएं सिमटती चली गई। देश के अधिकतर भागों में कृषि विकास दर काफी कम हो गई। किसान एक के

बाद एक आत्महत्या करते रहे। कृषि क्षेत्र में बढ़ी विकास दर के पीछे मध्यप्रदेश, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों का अच्छा प्रदर्शन रहा।

भ्रष्टाचार

यूपीए सरकार की छवि बिगड़ने की एकमात्र सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार है। राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के कारण प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आयोजन की वैधानिकता नष्ट हो गई। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। मंत्री, अफसर और लाभार्थी गिरफ्तार किये जाने हैं।

प्रधानमंत्री आखिरी दम तक घोटाले का बचाव करते रहे। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय और सीएजी ने प्रतिकूल टिप्पणियां कीं। सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दाखिल किये जा रहे हैं। यूपीए सरकार ने 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाले में भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये संयुक्त संसदीय समिति के निर्णय को पलटने की कोशिश की।

कोल ब्लॉक आबंटन में बेशकीमती राष्ट्रीय संसाधन की लूट की गई। बिजली अधिनियम, 2003 में बना था, जो ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों के लिए एक बड़ी पहल थी। आज अधिकतर बिजली संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता कम होती जा रही है। यूपीए इस घोटाले की गंभीरता को नहीं मान रही है। केन्द्र सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय सीबीआई जांच में निरंतर दखल दे रहे हैं और न्यायायिक संस्था के सामने रखी जा रही स्थिति रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई। सुधार का काम करने के बजाय यूपीए की कोशिशें है कि सच सामने नहीं आने पाए। रेलवे में नौकरी के बदले नोट घोटाला यूपीए को झटका देने वाला सबसे ताजा मामला है। रेलवे बोर्ड के बड़े पदों की परोक्ष रूप से मंत्रियों द्वारा नीलामी की जा रही है। मामले की तह में जाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि इस मामले में प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार राजनीतिज्ञों के खिलाफ धीमी गति से जांच की जाए।

संस्थायें

यूपीए की नीति सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अस्तित्व को घटाने की रही है। संवैधानिक और कानूनी संस्थाओं में नियुक्ति के मामले में जो सरकारी नीति अपनाई गई उसका मकसद उनके महत्व को कम करना रहा है। यूपीए का अस्तित्व सीबीआई पर निर्भर हो गया है। सीबीआई की नीति एक मददगार एजेंसी के रूप में सरकार की मदद करना हो गई है। यूपीए और उसके सहयोगी दलों के अपराधों को छिपाया जा रहा है।

सरकार के विरोधियों के प्रति बदले की कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों को लालच देकर और सीबीआई का शिकंजा कसने की नीति के तहत रखा जा रहा है। चाहे निर्वाचन आयोग हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या सीवीसी हो, उनके लिये यूपीए द्वारा की गई नियुक्तियां भारी संदेह के घेरे में हैं। इन संस्थाओं को बचाने के लिए न्यायपालिका तक को हस्तक्षेप करना पड़ा।

राष्ट्रीय सुरक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा की विफलता यूपीए की अकर्मण्यता का प्रतीक बन गई है। बार बार आतंकवादी हमले हो रहे हैं जिससे प्रतीत होता है कि भारत अब भी आतंकवादियों के निशाने पर सबसे उपर है। कई राज्यों में माओवादी हिंसा बेधड़क जारी है। यूपीए की आतंकवाद और घुसपैठ पर अंकुश लगाने की कोई स्पष्ट नीति नहीं है।

अस्थिर पड़ोस

कभी भी अपने पड़ोसियों के साथ इतने संकटपूर्ण रिश्ते नहीं रहे जैसे की आज हैं। पाकिस्तान भारत में बड़ी तादाद में आतंकवादियों के जरिये खून बहाने का जरिया बना हुआ है। भारतीय सैनिकों का सिर काटने और पाकिस्तानी जेल में भारतीय कैदियों को जान से मारने के साथ पाकिस्तान सीमा पर बार-बार उकसावे की कार्रवाई करने से बाज नही आ रहा है। चीन भारत पर दबदबा बनाये हुए है। नत्थी वीजा देना, भारतीय सीमा का अतिक्रमण करना, वास्तविक नियंत्रण रेखा को नहीं मानना, पिछले कुछ वर्षो से चीन के आक्रामक व्यवहार का हिस्सा बन गया है। भारतीय सीमा के साथ सड़क और बांध का निर्माण उकसावे की कार्रवाई है। लद्दाख में हाल में सरकार ने जिस तरह पर्दे के पीछे बातचीत और समझौते किये, उसे बताने में वह हिचकिचा रही है। यहां तक की मालदीव भी यह मानते हुये भारत की अवहेलना कर रहा है कि हिंद महासागर में उसकी अहम उपस्थिति है।

महिलाओं का उत्पीड़न

पिछले कुछ वर्षो में, महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर पहुंच गया है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तेजाब फेंकना रोजमर्रा की घटनाएं बन गई हैं। इस उत्पीड़न के खिलाफ खुलकर विरोध होने के बाद सरकार को मजबूरन कानून में संशोधन करना पड़ा, लेकिन जमीनी हकीकत में सुधार नहीं आया है। यूपीए सरकार का पिछले चार साल का सफर काफी निराशाजनक रहा है। देशभर में यूपीए को लेकर जो निराशा है भारतीय जनता पार्टी उसे लगातार उजागर करती रहेगी।■

संप्रग-2 के चार साल पूरे होने पर

समाचार-पत्रों ने कहा-

देश में निराशा का माहौल, पूरी तरह विफल संप्रग सरकार

संप्रग-2 के चार साल पूरे होने पर हिंदी के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों ने अपनी संपादकीय टिप्पणी में केंद्र सरकार की जमकर खबर ली है। इन टिप्पणियों में कहा गया है कि चार साल पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद डॉ. मनमोहन सिंह ने सौ दिन में महंगाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का वादा किया था। लेकिन, चार साल बाद भी सरकार उक्त दोनों मुद्दों पर पूरी तरह विफल साबित हुई। हम यहां कुछ समाचार-पत्रों की संपादकीय टिप्पणी के प्रमुख अंश प्रकाशित कर रहे हैं:

'दैनिक जागरण' ने शीर्षक दिया है -
'नाकामी की कहानी'

समाचार पत्र लिखता है- किसी भी ऐसी सरकार के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए बहुत कुछ हो सकता है जो पिछले नौ साल से सत्ता में हो, लेकिन अगर आम जनता उससे आश्वस्त नहीं होती तो फिर उसे चिंतित होना चाहिए। संप्रग सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने के मौके पर अपनी उपलब्धियों का जो गुणगान किया उसका कोई विशेष महत्व इसलिए नहीं, क्योंकि देश में निराशा का सा वातावरण छाया हुआ है। इस वातावरण के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार और उसके नीति-नियंता। पिछली सरकार की उपलब्धियों और कुछ आंकड़ों का सहारा लेकर केंद्र सरकार चाहे जितनी उजली तस्वीर पेश करने की कोशिश करे, सच्चाई यह है कि पिछले चार वर्षो का उसका कार्यकाल नाकामी की ही कहानी कहता है। उपलब्धियों का मतलब यह नहीं होता कि नौ साल तक सत्ता में रहते समय जो कुछ भी किया गया है उसे करीने से प्रस्तुत कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने अपनी दूसरी पारी की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की है। ज्यादा निराशाजनक यह है कि कहीं कोई यह महसूस करता हुआ नहीं दिख रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है और जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था वैसा नहीं किया गया।

यह विचित्र है कि तमाम नाकामियों से दो-चार होने के बावजूद आलोचकों को गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश से उसे शायद ही कुछ हासिल हो सके, क्योंकि आम जनता तक यह संदेश बहुत अच्छे से जा चुका है कि इस सरकार ने किसी भी मोर्चे पर कुछ भी उल्लेखनीय हासिल नहीं किया। बात चाहे अर्थव्यवस्था के मोर्चे की हो अथवा विदेश नीति के मोर्चे की या फिर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की या अन्य अनेक क्षेत्रों में सुधार करने की-हर तरह असफलताएं ही मुंह बाए खड़ी नजर आती हैं। ..... केंद्रीय सत्ता की चौथी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से जैसे विचार व्यक्त किए गए उससे यह नहीं लगता कि वे देश की नब्ज टटोल पाने में सक्षम हैं। प्रधानमंत्री की ओर से जो कुछ कहा गया उससे तो ऐसा लगता है कि अगले एक वर्ष में वह सब कर लिया जाएगा जो चार वर्ष में नहीं किया जा सका, लेकिन इसके आसार कम ही हैं। यदि केंद्र सरकार अपनी छवि में सुधार करना चाहती है और जो मौजूदा माहौल है उसे बदलने के लिए वास्तव में तत्पर है तो उसे सबसे पहले उन गलतियों को स्वीकार करना चाहिए जो उसके द्वारा की गई और जिनके चलते आम जनता के बीच गलत संदेश गया। केंद्र सरकार को इसका अहसास होना ही चाहिए कि उसकी साख पर आघात उसके अपने कार्यो से लगा है और इसके लिए किसी अन्य को दोषी ठहराना सच्चाई से जानबूझकर मुंह मोड़ने के अतिरिक्त और कुछ नहीं।

'नवभारत टाइम्स' का शीर्षक है -
'चार साल या चार जनम'

अखबार लिखता है - जहां तक सवाल इस सरकार की राजनीतिक जमीन का है तो इस बारे में कहने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है। समुद्र की लहरों की तरह एक के बाद एक

आती भ्रष्टाचार की खबरों के कारण बीते चार साल न सिर्फ सरकार, बल्कि देश के लिए भी दु:स्वप्न सरीखे गुजरे हैं। इन सभी मामलों में एक साझा बात यह थी कि इनसे जुड़ी सूचनाएं सरकार के ही किसी अंग, सीएजी या सीबीआई के जरिए सामने आईं। ..... भारतीय राज्य मशीनरी और इसे चलाने वाले मंत्रियों को लेकर देश में पहले भी कोई अच्छी राय नहीं रही है। लेकिन पिछले चार सालों में भ्रष्टाचार का जो ज्वालामुखी सा फूट पड़ा है, उसकी तीन वजहें हो सकती हैं।

एक, फैसलों को प्रभावित करने के लिए कंपनियां अभी जितनी बड़ी रकम देने को तैयार हैं, उसकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। दो, किन्हीं वजहों से भ्रष्टाचार को छिपाना अब काफी मुश्किल हो गया है (खिसियाने लहजे में आरटीआई का हवाला देकर सरकार इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है)। और तीन, या तो सरकार में शामिल लोग कुछ ज्यादा ही अनैतिक हैं, या फिर प्रधानमंत्री तथा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सत्ता के दो केंद्रों की मौजूदगी ने उन्हें ढीठ बना दिया है। आम लोगों की नजर इनमें से तीसरे वाले पहलू पर ही है।

'राजस्थान पत्रिका' का शीर्षक -
'और एक साल...'

पत्रिका का मानना है - चार साल के अपने दूसरे कार्यकाल में मनमोहन सिंह की सरकार कितनी कामयाब या नाकामयाब रही, इसका फैसला रिपोर्ट कार्ड की बजाय जनता करेगी। चार साल पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मनमोहन सिंह ने सौ दिन में महंगाई पर काबू पाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का वादा किया था। सौ दिन नहीं, चार साल बाद भी सरकार उस वादे पर खरा उतरना तो दूर, पूरी तरह विफल साबित हुई। यह राजनीति की विडम्बना ही है कि तमाम घोटालों और आम आदमी की उम्मीदों को धराशायी करने के बाद भी सरकार कामयाबियों का जश्न मना रही है। इन चार सालों में कांग्रेस के छह सहयोगी दल यूपीए गठबंधन छोड़ गए।

जाहिर है, सरकार से अलग होने के पीछे कुछ तो कारण रहे ही होंगे। संवैधानिक संस्थाओं को सरकार के हाथों की कठपुतलियां बनाए जाने को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत का सरकार को फटकार लगाना अच्छी बात नहीं है। सरकार आज उपलब्धियों का कितना भी बखान क्यों न कर ले, लेकिन हकीकत में देश की आम जनता अपने आपको ठगा महसूस कर रही है। .....

सरकार तेजी से बढ़ती महंगाई को नहीं रोक पाई, लेकिन उसे भ्रष्टाचार को रोकने से किसने रोका? मंत्रियों ने घोटालों में शामिल होकर और घोटालों को दबाने की कोशिश करके वास्तव में देश को खराब संकेत दिए हैं। ..... जनता को रोष केवल महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही नहीं है, काले धन के मामले में भी सरकार का रवैया सबसे निंदनीय रहा है।

'राष्ट्रीय सहारा' ने शीर्षक दिया है -
'चमत्कार का पलटवार'

समाचार पत्र कहता है - मनमोहन सिंह सरकार ने अपने कार्यकाल के लगातार नौ साल पूरे कर लिए हैं, यह अपने आप में बड़ा चमत्कार है। चमत्कार इसलिए कि यूपीए सरकार के इस दूसरे संस्करण में डीएमके, टीएमसी और झाविमो जैसे कई पुराने साथी मुंह फुलाकर किनारा कर चुके हैं। बावजूद, सरकार चौथा साल पूरा होने का जश्न इस यकीन के साथ मना रही है कि वह निर्धारित पांच साल का कोटा पूरा करके ही दम लेगी। चमत्कार इसलिए भी कि इन चार सालों के दरम्यान उसके कई प्रतापी मंत्री शर्मसार होकर कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हुए, एक से बढ़कर एक महाघोटालों ने देश को हिला कर रख दिया- अगर कोई नहीं हिला तो बस मनमोहन सिंह की सरकार, जो रिपोर्ट कार्ड में अव्वल होने का दावा करती हुई अपनी पीठ थपथपा रही है।

'नेशनल दुनिया' का शीर्षक है -
'चार साल की चांदनी'

समाचार-पत्र लिखता है - आम जनता के बीच भ्रष्टाचार को लेकर लगातार छीजती छवि के साथ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा साल भी पूरा कर लिया है। ...संप्रग के दूसरे कार्यकाल में बेतहाशा महंगाई, सुधारों की धीमी रफ्तार के कारण कमजोर होती अर्थव्यवस्था और चीन-पाकिस्तान की हरकतों की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा पर जब-तब खड़े होने वाले सवाल उसके लिए बड़ी चुनौती हैं।

पिछले एक साल में संप्रग के घटक दलों में बिखराव हुआ है। खासकर तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक जैसे बड़े घटक दलों का संप्रग से अलग होना उसके लिए बड़ा आघात माना गया। ■

भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और उसे छिपाने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण : राजनाथ सिंह

भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा 11 मई, 2013 को नई दिल्ली में दिया गया प्रेस वक्तव्य

यूपीए सरकार बड़े घोटालों के लिए बदनाम हो चुकी है। 550 खरब रुपये से ज्यादा के घोटालों के साथ यह आजाद भारत के इतिहास में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। मौजूदा सरकार के अनियंत्रित भ्रष्टाचार ने हमारे देश में शासन के लिए खतरा पैदा कर दिया है। दुर्भाग्यवश यूपीए की पूरी कोशिश अंत तक उन लोगों को बचाने की रही, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वह वह तभी सीमित कार्रवाई करती है, जब उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता।

भ्रष्टाचार और अनुचित कार्य करने के आरोपों का सामना कर रहे दो केन्द्रीय मंत्रियों ने कल रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री ने अगर इन दागी मंत्रियों को बिना किसी देरी के बर्खास्त किया होता, तो सरकार ने आसानी से बजट सत्र बचा लिया होता। 'खाद्य सुरक्षा' और 'भूमि अधिग्रहण' जैसे अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस होनी थी और इन्हें संसद में पारित किया जाना था लेकिन अड़ियल यूपीए ने इस अवसर को गंवाना पसंद किया।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से रेल मंत्री का बचाव किया उसे लेकर लोग अनेक सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री, रेल मंत्री को क्यों बचा रहे थे, जबकि उन्हें मालूम था कि उन्हें जाना पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी को रेल मंत्रालय करीब 17 साल के अंतराल के बाद मिला था और सबसे पहली चीज जो रेलवे के बारे में हमने सुनी, वह थी यात्री किराये में भारी बढ़ोतरी और मंत्रालय में प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार।

पूरी व्यवस्था खतरे में

भाजपा उच्चतम न्यायालय की केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बारे में की गई उस टिप्पणी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है, जिसमें उसे सरकार का ''रट्टू तोता'' कहा था। कानून मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य अधिकारियों के साथ अपनी रिपोर्ट को साझा करने के लिए सीबीआई को मजबूर किया गया, जबकि उच्चतम न्यायालय ने 'कोलगेट' घोटाले में उससे अदालत को सीधी रिपोर्ट देने को कहा था। श्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए सीबीआई से जबरदस्ती की। यूपीए सरकार द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को भ्रष्ट करने का यह बहुत गंभीर मामला है। इसने पूरी व्यवस्था की ईमानदारी और दायित्व पर अनेक गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। हमें हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को बरकरार रखने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद, न केवल कानून मंत्री कटघरे में खड़े थे बल्कि प्रधानमंत्री की भी ऐसी स्थिति हो गई जहां उनके लिए अपना बचाव करना मुश्किल था। कानून मंत्री और अन्य अधिकारियों ने ''रिपोर्ट से छेड़छाड़'' की जिसमें उस समय की चर्चा थी जब प्रधानमंत्री स्वयं कोयला मंत्रालय में थे। अगर अश्विनी कुमार को सीबीआई रिपोर्ट को प्रभावित करने के लिए जाना पड़ा तो प्रधानमंत्री कार्यालय को भी क्यों न इस मामले में जवाबदेह बनाया जाए?

चाहे 2जी घोटाला हो या 'कोलगेट' प्रधानमंत्री की भूमिका लंबे समय से संदेह के घेरे में है। 'रिपोर्ट से छेड़छाड़' कर सरकार ने प्रधानमंत्री को अलग करने का विफल प्रयास किया है, लेकिन श्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद पूरी सरकार की पोल खुल गई है। भाजपा का मानना है कि प्रधानमंत्री से ध्यान बंटाने के लिए श्री अश्विनी कुमार और श्री पवन कुमार बंसल को बलि का बकरा बनाया गया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में कानून मंत्री ने सीबीआई की कोलगेट रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ क्यों की? क्या यह उस अवधि के कोयला ब्लॉक आवंटन की विस्तृत जानकारी को छिपाने की कोशिश नहीं थी जब प्रधानमंत्री के पास कोयला मंत्रालय था? 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष श्री ए. राजा को उपस्थित होने की इजाजत क्यों नहीं दी गई?

प्रधानमंत्री जेपीसी के समक्ष उपस्थित होने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए, जबकि उन्होंने पीएसी के समक्ष उपस्थित होने की स्वयं पेशकश की थी? इन सवालों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं है।

यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है। पहले भी स्वर्गीय राजील गांधी और स्वर्गीय पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार स्थिति एकदम अलग है क्योंकि अब पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भारत की जनता का पूरी व्यवस्था पर से तेजी से विश्वास उठ रहा है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रुप में, भाजपा महसूस करती है कि भारतीय लोकतंत्र के सभी साझेदारों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए ताकि हमारी राजनीतिक प्रणाली की विश्वसनीयता को बहाल किया जा सके। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को यह मेरा सुझाव है कि वे आत्मविश्लेषण करें और फैसला करें कि पूरी राजनैतिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए वे क्या कर सकते हैं।

सरकार नैतिक ताकत पूरी तरह खो चुकी है और संख्या बल पर टिकी हुई है। यूपीए सरकार की संख्या बल के दो महत्वपूर्ण स्रोत उत्तर प्रदेश के दो दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है।

एसपी और बीएसपी से मेरी अपील है कि अगर वे व्यवस्था के पतन और लोगों के कष्टों से गंभीर रूप से चिंतित है, तो उन्हें यूपीए से तत्काल समर्थन वापस ले लेना चाहिए अन्यथा इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए वे भी समान रूप से जिम्मेदार होंगी।

यूपीए सरकार की विश्वसनीयता इतनी कम हो गई है कि श्री अश्विनी कुमार और श्री पवन बंसल की देरी से रवानगी उसे बहाल नहीं कर सकती।

चूंकि सरकार और उसके पूरे प्रतिष्ठान बहरी हो गई है और संसद में उठी आवाजें उसके कान में नहीं पड़ी हैं, इसलिए भाजपा ने फैसला किया है कि वह लोगों के पास जाएगी, यूपीए सरकार के ठीक से काम न करने, निष्क्रियता और आकंठ भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा देशभर में धरने देकर और जेल भरो आंदोलन के आह्वान के साथ 27 मई से 2 जून, 2013 तक जागरुकता अभियान चलाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में

यूपीए सरकार के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। पड़ोसी देशों के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बार-बार घुसपैठ हो रही है। हाल में लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में घुसपैठ इसका प्रत्यक्ष और संगीन उदाहरण है। चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने बिना किसी भय के तंबू गाड़ दिये। राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण करीब तीन हफ्ते यह मामला अनसुलझा रहा। हालांकि अब सरकार दावा कर रही है कि घुसपैठ का मामला चीन के साथ सुलझा लिया गया है। लेकिन मीडिया की खबरें हैं कि वह अनकहे समझौते के अंतर्गत हमारे कुछ रक्षा ढांचे (बंकर) ढहाने और चूमर घाटी में गश्त कम करने पर सहमत हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दे पर हम सरकार को पूरा नैतिक समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ है।

विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद चीन के सरकारी दौरे पर इस सप्ताह बीजिंग गए। हम उम्मीद कर रहे थे कि अपनी यात्रा के दौरान वे चीनी घुसपैठ के मुद्दे सहित कुछ अन्य मुद्दे भी उठाएंगे, लेकिन हमें यह जानकर निराशा हुई कि कूटनीतिक बातचीत के दौरान उन्होंने इन मुद्दों का जिक्र तक नहीं किया।

लद्दाख में पीएलए की घुसपैठ को एक अलग घटना के रुप में नहीं देखा जा सकता। अगर हम इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो तस्वीर अलग दिखाई देगी। ऐसा उदाहरण है जब चीन ने पाकिस्तान चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, पाक अधिकृत कश्मीर में अपने सैनिक तैनात किये, अभी भी अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, कई बार जम्मू-कश्मीर के निवासियों को स्टैपल्ड वीजा देता है, ब्रह्मपुत्र के बहाव में बाधा पहुंचाता है। इन सभी चीजों को उसके बड़े उद्देश्यों के रूप में देखा जाता है। भाजपा इन बातों पर यूपीए की नासमझी और भारत के सामरिक हितों की रक्षा के लिए प्रभावकारी कूटनीतिक उपाय नहीं करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। चाहे पाकिस्तान का मसला हो या चीन या नेपाल या श्रीलंका या यहां तक कि मालदीव का, यूपीए सरकार के अंतर्गत भारत का समूचा कूटनीतिक प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है।

एनडीए के शासनकाल में भारत की विदेश नीति की संरचना न केवल मजबूत और व्यावहारिक थी, बल्कि उसमें दूरदर्शिता और आदर्श थे। अब यूपीए सरकार उस संरचना को पूरी तरह नष्ट कर चुकी है। अगर यूपीए सरकार कमजोर और कूटनीतिक रणनीति के साथ सत्ता में बनी रही, मुझे आशंका है कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर देगी, जब नैटो सैनिक 2014 में अफगानिस्तान से वापस लाएंगे। ■

क्या उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई का महत्व घटाया है अथवा उसे मजबूत किया है

अरुण जेटली

श्री दिग्विजय सिंह के बारे में मशहूर है कि वे बेवक्त की बांसुरी बजाते हैं। उनकी हाल की यह टिप्पणी कि किसी मामले की सुनवाई करते समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसा आचारण करना चाहिए, न्यायिक संस्थानों को दी गई अनुचित सलाह है।

न्याय प्रक्रिया में सुधार और उच्चतम न्यायालय के फैसले पर बहस करना तो उचित है। फैसलों और आदेशों पर बहस की जा सकती हैं, क्योंकि अदालतें गलत हो सकती हैं। न्याय व्यवस्था के कामकाज में सुधार करने वाली आलोचना या टिप्पणी का हमेशा स्वागत है। लेकिन आलोचना किसी हारे हुए व्यक्ति की हताशा नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह के बयान में हताशा दिखाई देती है।

क्या न्यायाधीशों को हमेशा मौखिक टिप्पणियां करनी चाहिए?

यह टिप्पणी, न्यायाधीशों को केवल लिखित आदेश के जरिये ही अपनी बात कहनी चाहिए और मौखिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति ने की है जो अदालत के कामकाज से वाकिफ नहीं है। अदालतों में विस्तार से मौखिक दलीलें दी जाती हैं। दलीलें, कभी-कभार बहस का रुप ले लेती हैं। न्यायाधीशों के सवाल और टिप्पणियां संकेत देती हैं कि न्यायिक विचार किस तरीके से काम कर रहा है। वकील चुप रहने वाले न्यायाधीशों के बजाय हमेशा बोलने वाले न्यायाधीशों को पसंद करते हैं। एक न्यायाधीश के भ्रम में डालने वाले विचार, चाहे वह तथ्य से संबंधित हों या कानून से जुड़े, को सही करना हमेशा संभव होता है।

अदालत की अंतिम राय हमेशा पुख्ता होती है। जब एक सरकार या जांच एजेंसी गलत दिशा में जा रही होती है, मौखिक टिप्पणियां उसे सही दिशा में ले जाने के लिए की जाती हैं। अंतिम आदेश अदालत की सोच-समझकर दी गई राय को व्यक्त करता है। कोयला ब्लॉक आवंटन जांच जैसे मामले में मौखिक टिप्पणियों और विस्तृत लिखित आदेश के साथ न्यायिक सक्रियता जुड़ गई।

संयम और शासन कला दोनों ने, शासन न्याय विवेचना में योगदान दिया। अगर दिग्विजय सिंह की अदालत में न बोलने की नासमझ सलाह पर न्यायाधीश ध्यान दें, तो सुनवाई नीरस हो जाएगी और मामले में पूरी तरह न्याय नहीं हो सकेगा क्योंकि भ्रम में डालने वाले विचारों को सही करने का अवसर हाथ से निकल जाएगा।

संयम और शासन कला दोनों ने, शासन न्याय विवेचना में योगदान दिया। अगर दिग्विजय सिंह की अदालत में न बोलने की नासमझ सलाह पर न्यायाधीश ध्यान दें, तो सुनवाई नीरस हो जाएगी और मामले में पूरी तरह न्याय नहीं हो सकेगा क्योंकि भ्रम में डालने वाले विचारों को सही करने का अवसर हाथ से निकल जाएगा।

क्या उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई का महत्व घटाया है?

पिछले कुछ वर्षों में सीबीआई ने अपना महत्व कम किया है। सरकार ने इस प्रक्रिया में सक्रिय योगदान दिया है। सीबीआई की छवि रसातल में चली गई है। सीबीआई के निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जा रही है। सीबीआई में अधिकारियों के तबादले और उनकी नियुक्तियों को सरकार नियंत्रित कर रही है। मुकदमा चलाने की अनुमति भी सरकार द्वारा दी जा रही है। एजेंसी का इस्तेमाल राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ हो रहा है। सत्ता को लंबे समय तक बचाए रखने और समाजवादी पार्टी और बसपा के नेताओं को चुप कराने के लिए सरकार एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई, सरकार और सत्तारुढ़ पार्टी के बीच संबंध प्रगाढ़ हो गए हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति सीबीआई का निदेशक बन जाता है तो रिटायर होने के बाद उसके लिए अगले पद का पक्का इंतजाम हो जाता है।

कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी जांच में भी न्यायाधीशों को लगा कि एजेंसी निष्पक्ष और ईमानदार नहीं है। अदालत में दी गई उसकी स्थिति रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ की गई। सीबीआई ने रिपोर्ट का 'सार' ही बदल डाला। लगातार जिरह और मौखिक टिप्पणियों

के बाद सीबीआई ने माना कि कानून मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कोयला मंत्रालय ने रिपोर्ट से कुछ हिस्से निकाल दिये और रिपोर्ट में बदलाव किया। बदलाव महत्वपूर्ण थे। यहां दब्बू सीबीआई स्थिति रिपोर्ट को बदलने वाले संदिग्धों सहित कार्यपालिका से अत्यन्त प्रसन्न थी।

विनीत नारायण मामला सीबीआई को मजबूत बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय की पहली कोशिश थी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश तय किये, लेकिन पिछले 17 वर्षों में सरकार ने इन दिशा निर्देशों से बाहर निकलने के तरीके ढूंढ लिए। लोकपाल के गठन और एक स्वतंत्र सीबीआई बनाने का आंदोलन अभी तक सफल नहीं हुआ है। प्रत्येक चरण में सरकार धीमी और अनिच्छुक साबित हुई। राजनैतिक दबाव में जांच करने पर सीबीआई का महत्व कम हो गया। इसके विपरीत, न्यायालय ने जब सीबीआई की दुर्दशा देखी, उसकी जांच पर निगरानी रखना जरुरी हो गया।

दोषी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अधिकारी अभी इस बात के लिए जूझ रहे हैं कि वे क्या जवाब दें। सरकार घबराई हुई है। अदालत के आदेश से संकेत मिलता है कि या तो सरकार सीबीआई को बचाने के लिए एक वैधानिक योजना बनाए या अदालत विशेष दिशा निर्देश जारी करे। स्वतंत्र जांच हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की विशेषता है। अगर सीबीआई को अधिक स्वतंत्र बनाया जाए तो इसका महत्व घटेगा नहीं, बल्कि यह और मजबूत बनेगी।

यह अदालत का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि जांच स्वतंत्र हो। गुजरात में 2002 के दंगों में जांच राज्य पुलिस के अंतर्गत हुई। अदालत ने राज्य के पुलिस अधिकारियों वाले विशेष जांच दल को जांच का पहला आदेश दिया। जांच से संतुष्ट नहीं होने पर उच्चतम न्यायालय ने अपने विशेष जांच दल का गठन किया जिसमें राज्य से बाहर के अधिकारी शामिल थे। बाद में उस जांच पर टिप्पणियों के लिए अदालत के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की गई। दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने उस निगरानी का स्वागत किया। जब यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की सीबीआई द्वारा जांच की जाती है और उच्चतम न्यायालय उसकी निगरानी करता है तो उस जांच की निगरानी को संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य कहा जा रहा है। इस तरह की सहूलियत वाली दलीलों के लिए एक सार्थक बातचीत में कोई स्थान नहीं है। ■

(लेखक वरिष्ठ भाजपा नेता व राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं)

कांग्रेस का इतिहास हमेशा जनता को गुमराह करने का रहा है : धूमल

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने 22 मई 2013 को शिमला में कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा जनता को गुमराह करके सत्ता को प्राप्त करने का है। विधान सभा चुनावों से पूर्व में वे जमीनों के मामले में प्रदेश की जनता के समक्ष लगातार झूठ बोलकर जनता को धोखा देते रहे। प्रदेश की जमीने पूर्व में रहीं कांग्रेस की सरकारें बेचती रही और आरोप भाजपा पर मढ़ते रहे।

प्रो0 धूमल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की जमीने गैर हिमाचलियों को बेचने के लिए कांग्रेस सरकारों ने तरह तरह के हथकण्डे अपनाए और इसके लिए उन्होंने कानून को तोड़ने मरोड़ने से भी परहेज नहीं किया। बाहरी लोगों को जमीन बेची जा सके इसके लिए अपनी सरकारों के समय कांग्रेस नेताओं ने धारा 118 में पांच बार संशोधन किया। प्रो0 धूमल ने कहा कि विधान सभा के दौरान वर्तमान कांग्रेस सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि वर्ष 2003 से 2008 तक उनके शासनकाल के दौरान धारा 118 के तहत 2398 स्वीकृतियां दी गई और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में केवल 1649 स्वीकृतियां दी गई और इस दौरान जहां कांग्रेस सरकार के शासनकाल में 18069 वीघा जमीन धारा 118 के तहत दी गई वहीं भाजपा के शासनकाल में केवल 14900 वीघा जमीन दी गई। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल के दौरान प्रदेश हित को ध्यान में रखते हुए धारा 118 के तहत जमीन दी गई वही कांग्रेस के शासनकाल के दौरान व्यक्तिगत चहेतों के हितों को ध्यान रखते हुए जमीनें दी गई। इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि कांग्रेस शासनकाल में धारा 118 के तहत में बाहरी लोगों को बसाने के लिए अपार्टमैन्ट एक्ट के तहत बहुत ज्यादा स्वीकृतियां दी। जबकि भाजपा के शासनकाल में उद्योगों, हाईडल प्रोजैक्टों, टूरिजम को महत्व दिया गया। इससे स्पष्ट है कि अगर किसी ने हिमाचल को बेचा है तो वह कांग्रेस की सरकारें रही है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि सरकार स्पष्ट करे कि किन लोगों यह स्वीकृतियां दी गई और किसके प्रभाव में आकर दी गई। कांग्रेस को प्रदेश की जनता को लगातार झूठ बोलकर गुमराह करने के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले मण्डी लोकसभा उप चुनाव में जनता के सामने कांग्रेस सरकार के काले चिटठों को रखा जाएगा। ■

कांग्रेस के खाली ढोल की खुली पोल

✍ अम्बा चरण वशिष्ठ

कहावत है कि गले में पड़ा ढोल तो बजाना ही पड़ेगा। यह मजबूरी है। और यही मजबूरी है कांग्रेसनीत संप्रग सरकार की। इस 22 मई को संप्रग-2 ने नौ वर्ष पूरे कर लिये। उस दिन 'आम आदमी की सरकार' ने आम आदमी की जेब पर डाका डाल धूमधाम से एक बड़ा रात्रिभोज कर जश्न मनाया। उपलब्धियों का बड़े जोर-शोर से नगाड़ा बजाया गया। जनता का छः अरब रूपया खर्च कर अपनी श्उपलब्धियोंश् का खूब ढोल बजाया। मीडिया भी खुश, कांग्रेस भी खुश। यह अलग बात है कि इस ढोल में न जान थी, न तान थी न बान ही थी। इस बेसुरे बाजे से कान अवश्य पक रहे थे। सब से ऊपर, न तो आम आदमी की भागीदारी हुई और न ही उसने ही कोई उत्सुकता दिखाई।

कांग्रेस की तथाकथित 'उपलब्धियों' की हालत तो उस व्यक्ति से भी बदतर है जिसने अपने शैक्षणिक जीवन में तो सदा स्वर्ण पदक प्राप्त किये पर अन्त में चोरी का अपराध कर जेल की हवा खाई। या जिस शौर्यगाथा लिखने वाले वीर जवान ने देश के लिये नाम तो कमाया पर अन्त में किसी व्यभिचार में फंस गया। या उस यशस्वी नेता का जिसने राष्ट्र के लिये तो बहुत कुछ किया पर अन्त में स्वयं डूब गया भ्रष्टाचार के नर्क में।

वैसे भी कांग्रेस के पास 'उपलब्धि' के नाम पर है ही क्या? उसने किया ही क्या है? 2004 व 2009 के लोक सभा के चुनावों में वादे तो लम्बे-चौड़े कर मारे थे। 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। आज लगभग सभी प्रतिदिन की आवश्यक चीजों के दाम आसमान को छू रहे हैं। आज हालत यह है कि दाल-सब्जी व रोटी आम आदमी की पहुंच के बाहर हो गये हैं। आज न जीना ही सस्ता रह गया है और न मरना।

जो संप्रग सरकार आज तक गरीबी की परिभाषा तय करने में सफल नहीं हो सकी वह गरीबी क्या दूर कर पायेगी? सरकार ने अनेक सर्वे करवा कर देख लिये पर अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि कितने प्रतिशत लोग गरीबी के रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रह हैं। एक रिपोर्ट तो यह भी है कि देश की 60-70 प्रतिशत आबादी प्रतिदिन 25-25 रूपये पर ही अपना जीवनयापन करती है। हमारे देश के प्रधान मन्त्री व वित्त मन्त्री इन गरीबों का एक मानक बजट तो बनाकर दिखायें जिसके अनुसार इतने कम धन से कोई निर्धन व्यक्ति किस प्रकार समग्र व पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकता है।

इसका मुख्य कारण है इस सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र व किसान की लगातार उपेक्षा करना। आज सरकार उद्योगों को तो अनेक प्रकार की विशेष सहायता, रियायतें, सुविधायें व आकर्षण प्रदान कर रही है। उन्हें सब्सिडी दे रही है। पर कृषि क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है। यही कारण है कि आज कृषि एक लाभकारी पेशा नहीं रह गया है। किसान जहां भी, जब भी और जैसे भी सम्भव हो रहा है वह इस पेशे का परित्याग करता जा रहा है। इसी कारण अब तक के आंकड़ों के अनुसार 2009 से 17,368 किसान अपनी आर्थिक दुर्दशा व ऋणों के बोझ के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। पर इस 'आम आदमी की सरकार' को काई आत्मग्लानि नहीं होती। भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह के शब्दों में, आज देश का अन्नदाता भूखा है और आत्महत्या पर मजबूर।

वैसे भी कांग्रेस के पास 'उपलब्धि' के नाम पर है ही क्या? उसने किया ही क्या है? 2004 व 2009 के लोक सभा के चुनावों में वादे तो लम्बे-चौड़े कर मारे थे। 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। आज लगभग सभी प्रतिदिन की आवश्यक चीजों के दाम आसमान को छू रहे हैं। आज हालत यह है कि दाल-सब्जी व रोटी आम आदमी की पहुंच के बाहर हो गये हैं। आज न जीना ही सस्ता रह गया है और न मरना।

देश मंदी के दौर से गुजर रहा है। नौकरियां कम हो रही हैं। अनेक निजी प्रतिष्ठानों से लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। सरकार व्यवसाय व नौकरी के नये अवसर खोलने में अक्षम रही है जिससे हमारे नौजवानों में बेरोजबारी बढ़ती जा रही है।

यह सरकार हर क्षेत्र में असफल रही है। न्यायप्रेमी व न्याय के सम्मान करने वाले निर्दोष नागरिकों की जान व उसकी सम्पत्ति की रक्षा करने में यह सरकार विफल रही है। देश में पिछले

सालों में अनेक आतंकी घटनायें हुई हैं पर अधिकतर मामलों में यह अपराधियों को पकड़ने व उन्हें अपने किये की सजा दिलाने में अक्षम साबित हुई है। देश की सीमायें सुरक्षित नहीं हैं। आये दिन चीन व पाकिस्तान घुसपैठ करते रहते हैं। पाकिस्तान ने हमारी सीमा में घुसकर हमारे दो बहादुर जवानों के सिर काट दिये और आज तक नहीं दिये। सरकार पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव नहीं बना पाई कि पाकिस्तान के होश ठिकाने लग जायें। 26/11 के अपराधियों को सजा दिलवाये जाने में जो पाकिस्तान में शरण प्राप्त किये बैठे हैं उन्हें भारत के हवाले करने या उन्हें सजा दिलाने में यह सरकार विफल रही है। वह सब खुले आम पाकिस्तान में भारत के विरूद्ध जहर उगलते रहते हैं और भारत के विरूद्ध आतंकी घटनाओं की साजिशें रचते रहते हैं।

श्री खुर्शीद हाल ही में चीन के दौरे से लौटे तो वहां की आवभगत से इतने प्रफुल्लित हो उठे कि उन्होंने कह दिया कि वह तो चीन की राजधानी बीजिंग में ही रहना पसन्द करेंगे।

सच्चाई तो यह है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं- चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व नेपाल- उन सब से भारत के इतने कटु सम्बन्ध कभी नहीं रहे जितने कि आज इस संप्रग सरकार के समय हैं।

अब जब कि चुनाव के लिये एक वर्ष से भी कम का समय बचा है और उससे पहले भी हो सकते हैं तो सरकार को सीधे कैश ट्रांसफर की सूझी है। और कौन जाने, कहीं यह भी एक घोटाला ही न बन जाए जैसे कि मनरेगा बना है।

चुनाव की दृष्टि से ही सरकार अब किसी प्रकार खाद्य सुरक्षा व भूमि अधिग्रहण कानून भी बनाने की जल्दबाजी में है। दूसरी ओर महिला आरक्षण बिल व तेलंगाना राज्य गठन की जनता की अनेक वर्षों से लम्बित मांग की अनदेखी करती जा रही है हालांकि यह दोनों विषय कांग्रेस के 2009 के चुनाव घोषणापत्र के प्रमुख अंग थे।

श्री खुर्शीद हाल ही में चीन के दौरे से लौटे तो वहां की आवभगत से इतने प्रफुल्लित हो उठे कि उन्होंने कह दिया कि वह तो चीन की राजधानी बीजिंग में ही रहना पसन्द करेंगे। सच्चाई तो यह है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं- चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व नेपाल- उन सब से भारत के इतने कटु सम्बन्ध कभी नहीं रहे जितने कि आज इस संप्रग सरकार के समय हैं।

इस सब से ऊपर कांग्रेस के सफेद झूठ पर कालिख फेर रही है उसके पिछले चार साल में हुये भ्रष्टाचार के मामले जिसके कारण देश विश्व में अपना सिर ऊंचा नहीं कर सका है। मनमोहन सरकार भारत की भ्रष्टतम सरकार बनकर उभरी है। इस के कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचार के मामले सामने आये हैं उनकी गिनती रखना भी कठिन है क्योंकि जब तक यह अंक पाठकों के हाथ में होगा तब तक हो सकता है कि कोई नया स्कैम उजागर हो जाये।

उल्लेखनीय हैं कैश-फार-वोट कांड तथा अन्य अनेक घोटाले जैसे इराक से वोल्कर कांड तेल दलाली, नेवी वाररूम लीक मामला, गेहूं आयात, मनरेगा, डीडीए, सत्यम् प्रकरण, ए आर बालू मामला, एंट्रिक्स-देवास, 1.76 लाख करोड़ रुपये का 2जी स्पैक्ट्रम, 1.86 लाख करोड रुपये का कोल ब्लॉक आबंटन, राष्ट्रमंडल खेल, एयर इण्डिया के लिये वायुयान खरीदना अगस्ता-वेस्टलैंड वीवीआईपी हैलिकाप्टर व फार्म लोन आदि-आदि। इसके अतिरिक्त है रेल बोर्ड में नियुक्ति रिश्वत कांड व सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से छेड़छाड़ मामला जिस कारण प्रधान मन्त्री के बचाव के बावजूद रेल मन्त्री पवन बंसल व कानून मन्त्री अश्विनी कुमार को त्यागपत्र देना पड़ा।

हैरानी की बात यह है कि अरबों-खरबों के घोटाले हो गये और देश को चूना लग गया पर सरकार उसके लिये अपने आप को जिम्मेवार नहीं समझती। देश के अब तक के सब से बड़े कोयला घोटाले के लिये तो स्वयं प्रधान मन्त्री जिम्मेवार है क्योंकि यह सब गोलमाल तब हुआ जब कोयला मन्त्रालय उनके पास था। इसी कारण भाजपा व अन्य विपक्षी दल उनके त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं।

इन अनगिनत घोटालों व भ्रष्टाचार ने कांग्रेस की सफेद पोशाक पर और भी गहरी कालिख पोत कर रख दी है। अब तो उसकी शक्ल व छवि ही विकृत हो कर रह गई है। लोक सभा चुनाव चाहे अगले वर्ष हों या दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की विधान सभाओं के इसी वर्ष होने वाले चुनावों के साथ, उसके पास जनता से वोट मांगने के लिये कुछ नहीं बचा है। उस समय का इंतजार कर रही है, जब वह अपने साथ हुए विश्वासघात का हिसाब चुका के कांग्रेस को शासनविहीन कर दे। ■

(लेखक भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं)

भाजपा प्रदेश प्रभारियों एवं प्रकोष्ठ संयोजकों की घोषणा

भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने 19 मई 2013 को कार्यक्रम-कार्यान्वयन एवं समन्वय समिति, प्रदेश तथा मोर्चा प्रभारियों एवं सह-प्रभारियों, राष्ट्रीय संयोजकों और सह-संयोजकों की नियुक्ति की है, जिनकी सूची नीचे प्रस्तुत की जा रही है:

भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने श्री बंडारू दत्तात्रेय को राष्ट्रीय-उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है।

इसके अलावा, उन्होंने निम्नलिखित की भी नियुक्ति की है-

1. कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं समन्वय समिति
2. प्रदेशों के प्रभारी एवं सह-प्रभारी
3. मोर्चों के प्रभारी एवं सह-प्रभारी
4. प्रकोष्ठों के संयोजक एवं सह-संयोजक

श्री भूपेन्द्र यादव तथा श्री किरीट सोमैय्या राजस्थान प्रदेश में विधान सभा चुनावों तक विशेष सहायता प्रदान करने का कार्य करेंगे।

कार्यक्रम-कार्यान्वयन एवं समन्वय समिति

श्री एम.ए. नकवी-	समन्वयकर्ता
श्री जे.पी. नड्डा-	सदस्य
श्री श्याम जाजू-	सदस्य
श्री भूपेन्द्र यादव-	सदस्य
डॉ. सुधांशु त्रिवेदी-	सदस्य

प्रदेशों के प्रभारी तथा सह-प्रभारी

क्र. सं.	प्रदेश	प्रभारी	सह-प्रभारी
1.	उत्तर प्रदेश	श्री अमित शाह	श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत श्री रामेश्वर चौरसिया श्री सत्येन्द्र कुशवाहा
2.	मध्य प्रदेश	श्री अनन्त कुमार	
3	गुजरात	श्री ओ.पी. माथुर	
4.	राजस्थान	श्री कप्तान सिंह	
5.	कर्नाटक	श्री थावरचन्द गहलोत	
6.	हिमाचल प्रदेश	श्री बलबीर पुंज	
7	पंजाब	श्री शांता कुमार	श्री श्याम जाजू
8	चंडीगढ़	श्रीमती आरती मेहरा	
9	हरियाणा	श्री जगदीश मुखी	डॉ. अनिल जैन
10	उत्तराखंड	श्री राधा मोहन सिंह	
11	छत्तीसगढ़	श्री जे.पी. नड्डा	
12	बिहार	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	श्री विनोद पाण्डे
13	झारखंड	डॉ. रमापति राम त्रिपाठी	
14	ओडिशा	श्री चंदन मित्रा	श्री अरुण सिंह
15	गोवा	श्रीमती स्मृति ईरानी	
16	महाराष्ट्र	श्री राजीव प्रताप रूडी	
17	आंध्र प्रदेश	श्री प्रभात झा	
18	तमिलनाडु	श्री मुरलीधर राव	
19	केरल	श्री बंडारू दत्तात्रेय	
20	पुडुचेरी	श्री लक्ष्मण	
21	लक्षद्वीप	श्री पी. कृष्णदास	
22	अंडमान और निकोबार	श्री गणेशन	
23	पश्चिम बंगाल	श्री वरुण गांधी	श्री सिद्धार्थनाथ सिंह
24	असम	श्री एस.एस. अहलुवालिया	
25	मेघालय	श्री किरण रिजीजू जी	
26	नगालैण्ड	श्री तापिर गांव	
27	अरूणाचल प्रदेश	श्रीमती बिजया चक्रवर्ती	
28	मिजोरम	श्री नलिन कोहली	
29	मणिपुर	श्री तापिर गांव	
30	जम्मू और कश्मीर	श्री अविनाश राय खन्ना	सरदार आर.पी. सिंह

मोर्चों के प्रभारी एवं सह-प्रभारी

महिला मोर्चा	-	श्रीमती मृदुला सिन्हा
युवा मोर्चा	-	श्री पी. मुरलीधर राव
अनुसूचित जाति मोर्चा	-	श्री सत्यनारायण जटिया
अनुसूचित जनजाति मोर्चा	-	श्री जुएल ओराम
किसान मोर्चा	-	श्री पुरूषोत्तम रूपाला
अल्पसंख्यक मोर्चा	-	डॉ. जे.के. जैन

सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के समन्वयक श्री महेन्द्र पाण्डे

प्रकोष्ठ के संयोजक एवं सह-संयोजक

संगठक: किसान मोर्चा, पंचायत प्रकोष्ठ एवं गोवंश प्रकोष्ठ- श्री हृदयनाथ सिंह

संगठक: सहयोग, वरिष्ठ नागरिक, अंत्योदय योजना, एनजीओ प्रकोष्ठ- श्री माखन सिंह

संगठक: अनु.जाति मोर्चा, अनु.जनजाति मोर्चा एवं सहकारिता प्रकोष्ठ- श्री भगवतशरतण माथुर

संगठक: प्रशिक्षण एवं सहयोग निधि- श्री रामप्यारे पांडेय

क्र. सं.	नाम	संयोजक	सह-संयोजक
1	चुनाव	श्री आर. रामाकृष्णन	श्री पी.डी. गुप्ता, अधिवक्ता श्री राजन खोसला, अधिवक्ता श्री गणेश मालवीय श्री एम.एच. श्रीधर

2	प्रशिक्षण	श्री अलोक कुमार	श्री रामप्यारे पाण्डे
			श्री एल. गणेशन
			डॉ. एस.एस. अग्रवाल
3	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)	श्री अरविन्द गुप्ता	श्री विनीत गोयनका
			श्री संजीव सिंह
			श्री अमरीश माडविल
4	पंचायत राज	श्री मोहन सिंह ग्रामवासी	श्री योगेश शुक्ला
			श्री विनय रोहिल्ला
			श्री रजनीश-बिहार
			श्री इरेना कडाडी
5	नगर स्थानीय निकाय		
	प्रभारी- श्री सुरेश कुमार		श्री विजेन्द्र गुप्ता
6	कला एवं संस्कृति		
		डॉ. मिथिलेश कु. त्रिपाठी	श्री मोहन यादव
			श्री गजेन्द्र सोलंकी
			श्री रवि सतीजा
7	सहकारिता	श्री भंवर सिंह शेखावत	श्री लक्ष्मण सावित्री
	प्रभारी- श्री संतोष गंगवार		श्री ओम बिड़ला
			श्री अशोक ठाकुर
8	उद्योग	श्री नीरज तायल	श्री प्रणव टेकचन्द
	प्रभारी- श्री रवि विग		श्री अरुण बंसल
			श्री शिव शंकर शर्मा
9	माइक्रो तथा लघु	उद्योग श्री रजनीश गोयनका	श्री अवनीश दलाल
			श्री सुरेश खण्डेलवाल
			श्री एस. प्रकाश
10	व्यापार	श्री श्याम बिहारी मिश्रा	श्री घनश्याम अग्रवाल
			श्री अशोक गोयल
			श्री राजकुमार भाटिया
11	निवेश	श्री अतुल गर्ग	श्री चन्द्रशेखर शर्मा
			श्री शैलेन्द्र शर्मा
			श्री शुभेन्दु शेखर
12	खेल	श्री अशोक अग्रवाल	श्री श्रीप्रकाश पहलवान
	प्रभारी- श्री मोहिन्द्र लाल		श्री नरेन्द्र राणा
			श्री सुनील गुप्ता
			रंजन अय्यप्पा
13	पूर्व-सैनिक	ब्रि. बी.डी. मिश्रा	कैप्टन करण सिंह भाटी
14	मेडिकल	डॉ. महेश शर्मा	कैप्टन परमवीर
	प्रभारी- श्री सी.पी. ठाकुर		कैप्टन विकास गुप्ता
			डॉ. एन.एस. त्यागी
			श्री राहुल मिश्रा
			डॉ. आदित्य
			डॉ. जीवन्नावर
15	सहयोग	श्री सुरेश श्रीवास्तव	श्री महेश चड्डा
			श्री नवीन सिन्हा
			डॉ. राम सागर सिंह
16	वरिष्ठ नागरिक		
	प्रभारी- श्री बलराम दासजी टंडन		
		श्री अरूण जैन	श्री जयंती भाई बरोट
			श्री जगदीश मित्तल
17	अंत्योदय योजना (एनजीओ)	श्री बसंत कुमार	श्रीमती मेधा सोमैय्या
			श्री संजय चतुर्वेदी
	प्रभारी- ललिता कुमार मंगलम		श्री जितेन्द्र महाजन
18	पूर्वोत्तर भारत सम्पर्क प्रभारी	श्री सुनील देवधर	
	प्रभारी- पी. आचार्य		
19	जल-प्रबंधन	श्री श्रीराम वेदिरे	श्री उमेश ठाकुर
			श्री माधव भण्डारी
			श्री गंगप्पा
20	गौ-संवर्धन	श्री मयंकेश्वर सिंह	
	प्रभारी- श्री राधेश्याम गुप्ता		
21	मछुआरा	डॉ. प्रकाश मालगवे	श्री लालजी मैदान
			श्री राम चरित्र निषाद
22	गैर-पारम्परिक ऊर्जा		
		श्री एम.के. अन्ना पाटिल	श्री कृष्ण कुमार (कुमार साहब)
			श्री वाई.बी. रामकृष्ण
			श्री आलोक भार्गव
23	चार्टर्ड-एकाउण्टेंट्स		
		श्री सुनील वशिष्ठ	श्री संजय कपूर
			श्री दीनदयाल अग्रवाल
			श्री अखिलेश जैन
			श्री जी.वी. कृष्णा
			श्री ओ.पी. मिश्रा
24	विदेश मामले	श्री शेषाद्रीचारी	प्रो. शेषगिरी राव
25	विधि एवं विधायी		
	प्रभारी- श्रीमती पिंकी आनन्द		
		श्री राघवेन्द्र सिंह	श्री के. बाला सुब्रह्मण्यम
			श्री विवेक गोयल
			श्री विवेक रेड्डी
			श्री नीरज गुप्ता
26	साहित्य एवं प्रकाशन		
	प्रभारी- श्री प्रभात झा		
		श्री अम्बा चरण	डॉ. अनुपम आलोक
27	बुनकर	श्री विजय कुमार भारती	श्री मंगल सिंह कोरी
			मो. अली आजाद अंसारी
28	कामगार	श्री विश्वनाथन	श्री सुनील जोशी
			श्री धर्मपाल प्रजापति
29	ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी	श्री विजय जौली	श्री अमित ठक्कर
			डॉ. रजनी शरण
30	सूचना-अधिकार	श्री विवेक कु. गर्ग	श्री हरिओम अग्रवाल
31	फ्रैंड्स ऑफ बीजेपी		
		श्री राजेश जैन	श्री मनोज अरोड़ा
			श्री अमित मालवीय
			श्री रघु राम
32	झुग्गी झोंपड़ी	श्री अरुण देव जी	श्री सुनील भराला, मध्य प्रदेश
33	प्राकृतिक चिकित्सा		
		श्री जयप्रकाश अग्रवाल सूर्या	
			डॉ. डी.एन. शर्मा
34	संवाद	श्री अनुपम त्रिवेदी	श्री पारितोष व्यास
35	मीडिया	श्री श्रीकांत शर्मा	श्री के.के. शर्मा
			श्री हंस भल्ला
			श्री शिल्प कुमार

शेष पृष्ठ 24 पर

विश्वास खो चुके हैं प्रधानमंत्री

✍ बलबीर पुंज

कोयला घोटाले पर सर्वोच्च न्यायालय में हालिया घटनाक्रम के बाद, किसी भी प्रधानमंत्री में यदि गैरत होती तो वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री मनमोहन सिंह शीर्ष न्यायालय द्वारा उनकी सरकार की वास्तविकता देश के समक्ष जाहिर कर दिए जाने के बाद शेष बचा नैतिक आधार भी खो चुके हैं। जैसा कि हम अब जानते हैं कि, केंद्र सरकार सीबीआई को मिली घोटाले संबंधी जानकारियों को हटाने के लिए उस पर दबाव डालकर कोयला घोटाले में संलिप्त अपने शीर्ष स्तरीय पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही थी। यह मामला अन्य कई घोटालों की फेहरिस्त के बाद सामने आता है, जिनमें शामिल लोगों की श्रृंखला सत्ता के शिखर तक जाती है, और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को जायज बनाती है।

दुनियाभर में प्रधानमंत्रियों ने मामूली मुद्दों पर पदत्याग दिया है क्योंकि उनकी मूल प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति होती है। इस देश में, हालांकि, कांग्रेस का शासन एक पारिवारक मामला है। स्वाभाविक रूप से, नैतिक दायित्व का मुद्दा उन लोगों के लिए चिंता का कारक नहीं होता जो देश को परिवार की जागीर समझते हैं। श्री सिंह की हालत आज त्रासदीपूर्ण है। प्रधानमंत्री में प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने का साहस भी नहीं है और, इसके बजाए, वो संसद के उच्च सदन में स्थान प्राप्त करने की तलाश में हैं- और वो भी असम से जहां से उनका कोई नैसर्गिक जुड़ाव नहीं है। कांग्रेस में अभी भी श्री सिंह को लोकसभा के लिए चुने जाने हेतु प्रत्यक्ष चुनाव में उतारने का साहस नहीं है जिसके एक या दो निष्कर्ष हो सकते हैं: या तो श्री सिंह एक लोकप्रिय नेता नहीं है या कांग्रेस एक नामित प्रधानमंत्री चाहती है जिसे पार्टी अध्यक्षा के नियंत्रण के अधीन रखा जा सके।

यह सामान्य समझ की बात है कि यदि कोयला खंडों के आवंटन में घपलेबाजी हुई, तो वह प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना नहीं हो सकती थी क्योंकि उस समय कोयला मंत्रालय पीएम के पास ही था। यह सच्चाई, कि सीबीआई को शीर्ष न्यायालय के समक्ष स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा, उस प्रारूप को जाहिर करती है जिसे तत्कालीन कानूनमंत्री, भारत के महान्यायवादी और पीएमओ के अधिकारियों ने साथ मिलकर अभियान को ढकने के लिए अंजाम दिया।

प्रधानमंत्री एक बार फिर संसद में राज्यसभा के माध्यम से प्रवेश करने के प्रयास में हैं जो कि ऐसे समय पर हो रहा है जब अन्य बहुत सी घटनाओं ने उनकी कमजोर हालत को उजागर किया है। जब यह खबर आयी कि उनके तत्कालीन कानून एवं न्यायमंत्री अश्विनी कुमार ने सीबीआई के अधिकारियों को तलब किया था और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जांच एजेंसी द्वारा तैयार की गयी कोयला खंडों के आवंटन संबंधी रिपोर्ट में बदलाव किया था, श्री सिंह इस बात पर अड़े रहे कि मंत्रियों ने कुछ भी गलत नहीं किया और वे त्यागपत्र नहीं देंगे। जब सीबीआई को सरकार के हस्तक्षेप की बात स्वीकार करनी पड़ी, तब न्यायालय की टिप्पणियों के चलते संप्रग सरकार घेरे में आ गई। फिर भी प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार करने से इनकार किया कि श्री कुमार को जाना चाहिए। केवल जब रेलमंत्री पवन कुमार बंसल के पीछे भारी रिश्वतखोरी की श्रृंखला के खुलासे के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोते की संज्ञा देते हुए लताड़ लगायी गई तो सरकार को दोहरा झटका लगा और उसने बचने का प्रयास शुरू किया।

यह सामान्य समझ की बात है कि यदि कोयला खंडों के आवंटन में घपलेबाजी हुई, तो वह प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना नहीं हो सकती थी क्योंकि उस समय कोयला मंत्रालय पीएम के पास ही था। यह सच्चाई, कि सीबीआई को शीर्ष न्यायालय के समक्ष स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा, उस प्रारूप को जाहिर करती है जिसे तत्कालीन कानूनमंत्री, भारत के महान्यायवादी और पीएमओ के अधिकारियों ने साथ मिलकर अभियान को ढकने के लिए अंजाम दिया। 26 अप्रैल को सीबीआई द्वारा दिए कबूलनामे के बाद अब शीर्ष अदालत को पता चला है कि कोयला घोटाला रिपोर्ट में बदलाव किए गए, जो इसे रेखांकित करता है।

यह देखते हुए, कि श्री कुमार ने

अपने पद के लिए आभार श्री सिंह के प्रति व्यक्त किया जिन्होंने हर तरह से उनका बचाव किया, यह प्रमाणित होता है कि दो और दो को साथ रखा गया है, जिस तरह पूर्व कानून मंत्री और किसी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का बचाने का प्रयास कर रहे थे। यदि दोषी व्यक्ति पदानुक्रम में काफी निचले स्तर पर होता, तो कानून मंत्री ने ऐसा जोखिम न उठाया होता। जब इस बचाव अभियान के सूत्रधार पद से हटा दिए गए, सवाल अभी भी कायम है: उस दोषी को क्या कहा जाए जिसे श्री कुमार बचाना चाहते थे? सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, वह व्यक्ति और कोई नहीं स्वयं श्री सिंह हैं। चाहे कुछ भी हो, लोकतांत्रिक परंपरा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के लिए या नैतिक कम के लिए उनके प्रभार में है, और संबंधित राजनीतिक मुखिया जिम्मेदारी लेता है और पद छेड़ देता है। यह भी, जबकि कोयला घोटाले में रिश्वत देने वाले कुछ लोगों का पता चल गया है, यही बात रिश्वत लेने वालों के बारे में नहीं कही जा सकती। वे अभी भी परदे के पीछे छिपे हुए हैं। उनमें से किसी एक की भी अभी तक पहचान और उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई? यह

~~~~~~~~~~

यदि दोषी व्यक्ति पदानुक्रम में काफी निचले स्तर पर होता, तो कानून मंत्री ने ऐसा जोखिम न उठाया होता। जब इस बचाव अभियान के सूत्रधार पद से हटा दिए गए, सवाल अभी भी कायम है: उस दोषी को क्या कहा जाए जिसे श्री कुमार बचाना चाहते थे? सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, वह व्यक्ति और कोई नहीं स्वयं श्री सिंह हैं।

~~~~~~~~~~

स्पष्ट होता जा रहा है कि यदि सच्चाई को सानमे आना होगा, तो यह सरकार और प्रधानमंत्री पद पर बने नहीं रह सकते।

पिछले चार वर्षो से कांग्रेस रोज यह राग अलापती रही है कि श्री सिंह का ईमानदारी व सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण रिकार्ड रहा हैं यदि ऐसा है, तो फिर वो अरक्षणीय का बचाव क्यों करते हैं? इसके केवल दो कारण हो सकते हैं: पहला, चूंकि कोई भी सक्षम राजनेता बिना किसी कारण के बलि का बकरा कभी नहीं बनना चाहेगा, मगर श्री सिंह जानते हैं कि उन्हें अपने उस संरक्षक का बचाव करना है जो उनकी पैरोकारी करता है। यदि वो ऐसा करने में विफल हाते हैं तो वही संरक्षक उनके खिलाफ हो जाएगा।

एक और विश्वसनीय दलील यह है कि श्री सिंह ने कोयला मंत्री की हैसियत से स्वयं से ज्यादा शक्तिशाली किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर काम किया। वर्तमान व्यवस्था में वह शक्तिशाली व्यकित कौन हो सकता है? जबकि राज्यसभा मे उनका कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है और वो संसद की अपनी सदस्यता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी हाईकमांड पर निर्भर हैं, शायद श्री सिंह के सामने कुछ ही विकल्प शेष रह गए थे।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाला सरीखे अन्य घोटाले हैं, जहां श्री सिंह का नाम भी उछला है। कांग्रेस, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित अपने व्यक्ति, पीसी चाको के माध्यम से 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर निगाह लगाए हुए हैं और श्री चाको, प्रधानमंत्री को बचाने का प्रयास करते रहे हैं, जबकि समिति में सभी गैर कांग्रेसी सदस्यों ने उनका अनुसरण करने से इनकार दिया है। हालांकि, इन मामले में भी, यदि श्री

~~~~~~~~~~

2जी स्पेक्ट्रम घोटाला सरीखे अन्य घोटाले हैं, जहां श्री सिंह का नाम भी उछला है। कांग्रेस, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित अपने व्यक्ति, पीसी चाको के माध्यम से 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर निगाह लगाए हुए हैं और श्री चाको, प्रधानमंत्री को बचाने का प्रयास करते रहे हैं, जबकि समिति में सभी गैर कांग्रेसी सदस्यों ने उनका अनुसरण करने से इनकार दिया है।

~~~~~~~~~~

चाको, 10 जनपथ से इशारा मिलने पर प्रधानमंत्री का बचाव करने का इरादा छोड़ देते हैं तो श्री सिंह घेरे में आ जाएंगे। यहां तक कि कांग्रेस की पूर्व सहयोगी, द्रमुक, ने भी अब जेपीसी में यह मांग करने के लिए विपक्ष का समर्थन किया है कि गलत को गलत कहा जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी ही पार्टी द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है, और इसलिए स्वयं को, अपनी सरकार को और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रथम परिवार को बचाने के लिए श्री सिंह को अपने प्रशासन से बाहर मौजूद शक्तियों के निर्देशों का पालन करना होगा।

जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वयं इतने कमजोर हैं, तो फिर प्रशासन के मामले में देश उन पर भरोसा कैसे कर सकता है? सवाल यह नहीं है कि उनके पास संसद में बहुतमत है। यह व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक सत्यनिष्ठा और देश की सुरक्षा का मामला भी है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर रही है।

(पॉयोनियर से साभार)

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य हैं)

मात्र राजनयिक सम्बंध ही नहीं, भारत-चीन के बीच दृढ़ विश्वास बने

राम प्रसाद त्रिपाठी

चीन के नए प्रधानमंत्री ली कछियांग ने इस वर्ष मार्च में सत्ता संभालने के बाद पहली बार अपनी विदेश यात्रा पर 19 मई को भारत की तीन दिन की यात्रा पर आए। भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के दौरान उन्होंने भारत-चीन संबंधों के बारे में बयान देते हुए कहा कि ''हमारे संबंध अत्यंत स्नेहपूर्ण हैं तथा आशा और विश्वास को जगाती है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के सहयोग का मतलब है कि हम दोनों ही अपनी सभ्यताओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं, दोनों देशों के बाजार एक-दूसरे के पूरक हैं। हमारे दोनों देशों की उभरती अर्थव्यवस्थाएं समान विकास की पूर्ति करती हैं तथा दोनों पड़ोसी देश परस्पर लाभ प्राप्त कर नए-नए परिणामों के भागीदार बन सकते हैं।''

ली ने आगे कहा कि चीन भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार और मित्र समझता है और यह विश्वास भी अभिव्यक्त किया कि मेरी इस यात्रा से आपसी विश्वास, गहन सहयोग, समान हितों का विस्तार और द्विपक्षीय मित्रता मजबूत होगी जिससे शांति और समृद्धि के लिए चीन-भारत रणनीतिक सहकारी भागीदारी की भावना को और अधिक बल मिल पाएगा।

ली ने यह बात भी स्पष्ट शब्दों में कही कि ''मेरी वर्तमान भारत यात्रा के तीन उद्देश्य हैं- हम आपसी विश्वास बढ़ाएं, सहयोग मे तेजी लाएं तथा भविष्य की चुनौतियों का सामना करें।'' दोनों देशों ने व्यापार, कृषि, पर्यावरण संरक्षण और संस्कृति में सहयोग करने के बारे में अनेकानेक समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने चीन के प्रधानमंत्री ली के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारे बीच पहली बैठक है और हम दोनों ही द्विपक्षीय सम्बंधों को मजबूत करने के लिए उच्च-स्तरीय बातचीत का दौर जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ''चीन का नया नेतृत्व अच्छे पड़ोसी सम्बंध बनाने के लिए गम्भीर है और हम दोनों देशों के बीच सभी शेष मुद्दों का व्यावहारिक एवं परिपक्व समाधान करना चाहता है।''

दोनों पक्षों की तरफ से मित्रतापूर्ण तथा राजनयिक सद्व्यवहार की बात किए जाने पर भी, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सम्बघों के बहुत से मूलभूत प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सका है। सीमा पर फैला भ्रम और हाल में हुई लद्दाख में घुसपैठ के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसी प्रकार, उत्तरी क्षेत्र के हमारे फौजी कमाण्डरों को वीजा देने की इंकारी, और अरूणाचल एवं देसपांग के भारतीयों को स्टेप्ल्ड वीजा सम्बंधी घटनाओं पर भी चीन की तरफ से कोई भरोसेमंद उत्तर नही दिया गया। क्या भ्रम के वातावरण में दोनों देशों की द्विपक्षीय सम्बन्धों में कोई सुधार आ सकता है? चीन के प्रधानंमत्री की भारत की यात्रा से अभी कुछ दिन पूर्व ही चीन तथा भारत के बीच सीमा पर जिस प्रकार का गतिरोध बना रहा और दोनों पड़ोसियों के बीच आपसी विश्वास की कमी रही, क्या वास्तव में इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता पैदा हो सकती है?

दोनों पक्षों की तरफ से मित्रतापूर्ण तथा राजनयिक सद्व्यवहार की बात किए जाने पर भी, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सम्बघों के बहुत से मूलभूत प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सका है। सीमा पर फैला भ्रम और हाल में हुई लद्दाख में घुसपैठ के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इन दो महान देशों के बीच हाल के गतिरोध का उत्तर पाने के मामले में विस्तार से जाने से पूर्व यह जानना महत्वपूर्ण है कि ऐसे बहुत से बकाया द्विपक्षीय मुद्दे है जिनका सम्बंध भारत और चीन के बीच पर्वतों तथा नदियों से जुड़ा है, जिनका समाधान आवश्यक है। आक्रामक चीन के साथ व्यवहार करने में द्विपक्षीय सम्बंधों में सुधार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके कारण इन दो प्राचीन देशों के बीच अविश्वास तथा वैमनस्य का वातावरण पैदा होता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक स्थायी समस्या बना हुआ है। अब तक भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर 15 दौर की बातचीत हो चुकी

है परन्तु इनसे कोई लाभदायक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत ने सदैव ही अक्साई चीन क्षेत्र में चीन द्वारा 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया है, जबकि चीन सदा ही भारत के अरूणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर पर अपना दावा करता रहा है। हाल ही में, चीन ने पूर्वी लद्दाख में दौलतबेग ओल्डी (डीबीओ) में चीनी प्लाटून के टैंट गाड़ दिए थे जिसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था।

दूसरे, एक और बड़ा मुद्दा है तिब्बत जिसके कारण चीन के साथ द्विपक्षीय सम्बंधों में तनाव पैदा रहता है। चीन ने तिब्बत के आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा एवं भारत के 1,50,000 तिब्बतवासियों की उपस्थिति पर आपत्ति की है। दलाई लामा का मानना है कि वह तिब्बतवासियों के लिए और अधिक स्वायत्तता चाहते हैं जबकि चीन भारत और लामा पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाता है और उसका कहना है कि यह तिब्बत को चीन से अलग करने की साजिश है।

विवाद का तीसरा बिन्दु पाकिस्तान/चीन द्वारा पाकिस्तान को दिया जा रहा बेबाक समर्थन भी दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करता है। चीन पाकिस्तान हथियारों की सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है। हाल ही में, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को चीन को सौंप दिया था। इससे पूर्व 2012 में, पाकिस्तान ने काराकोरम में राजमार्ग बनाने की अनुमति दे दी थी जो क्जिंगजियान और पाकिस्तान के बीच की भूमि को जोड़ने की रणनीतिक चाल है।

बढ़ता व्यापार असंतुलन भी दोनों देशों के बीच उत्तेजना पैदा करता है। भारत का मानना है कि व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में कहीं अधिक है। भारत के प्रधानमंत्री ने चीनी प्रधानमंत्री ली कछियांग से व्यापार असंतुलन का समाधान करने के लिए कहा है जिससे चीन के साथ भारत को 29 बिलियन डालर का घाटा होता है।

एक और प्रमुख विवाद दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में चीन का शक्तिशाली देश बनने का है। चीन पड़ोसी देशों में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाकर भारत से अधिक शक्तिशाली होने की कोशिश कर रहा है। चीन ने बर्मा, बांग्लादेश, सीशेल्स और श्रीलंका में अपनी नौसेना सुविधाएं बना ली हैं। चीन पूर्वी अफ्रीका, केन्या में लामू और तंजानिया में बागामोचो में बंदरगाह विकसित कर रहा है। कुछ खबरों के अनुसार चीन ने हाल ही में नेपाल में सड़कों का निर्माण किया और 22-किलोमीटर सड़कें पूरी कर ली है जिससे चीन में कीरोंग जिले के साथ सेंट्रल नेपाल जुड़ गया है। हाल के वर्षो में भारत और चीन के बीच ये कुछ विवाद के विषय रहे हैं।

इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने की बजाए चीन ने एलएसी में भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का मुद्दा उठा दिया। वास्तव में चीन की फौजों ने देसपांग में हाल के गतिरोध में लद्दाख के अंदर 19 कि.मी. तक की घुसपैठ कर ली थी। वास्तविकता यह है कि भारत के लद्दाख में पिछले कुछ वर्षो में दौलतबेग ओल्डी (डीबीओ), न्योमा और फुकचे सहित कुछ हवाई क्षेत्रों का अपग्रेड किया था ताकि पहुंच से परे एलएसी में अपने फौजियों को संरक्षण दिया जा सके। अधिकांश फार्वर्ड पोस्ट हवाईयात्रा वाली ही है और हवाई क्षेत्र वहां आपूर्ति पहुंचाने के लिए परिवहन विमानों के लिए जीवन रेखा होती हैं।

संयोगत:, डीबीओ एयरफील्ड फेस ऑफ प्वाइंट है तथा चीन ने इस पर आपत्ति जताई थी। बीजिंग सीमा से अपनी गतिविधियां रोकने की बजाए, उसने भारत से अपना निर्माण बंद करने के लिए कहा है जबकि एलएसी में बीजिंग का कहीं उत्कृष्ट इफ्रांस्ट्रक्चर बना हुआ है।

एक तरफ तो चीन ने भारत में अपने प्रधानमंत्री की पहली यात्रा का चुनाव कर इस बात का संकेत दिया है कि बीजिंग भारत के साथ अपने सम्बंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है तो दूसरी तरफ चीन हाल के इन वर्षो में भारत को निशाना बनाकर भारत-विरोधी गतिविधियां जारी रखे हुए है।

राजनयिक अविश्वास होते हुए भी हाल के वर्षो में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कई गुना बढ़ा है, जो 2012 में 66.5 बिलियन यूएस डालर आंकड़े को छू गया है जिससे चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार का पार्टनर बन गया है। यदि चीन भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने की भूमिका अपना ले तो दोनों देशों के बीच 2015 तक 100 बिलियन डालर का द्विपक्षीय व्यापार भी संभव दिखाई पड़ता है। इससे दोनों देशों की विकसित अर्थव्यवस्था की स्थिति लाभकारी बन सकती है और ये दोनों महान एशियाई पड़ोसी देशों की समृद्धि फल-फूल सकती है।

भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी ली की यात्रा का स्वागत किया है और कहा है कि 'प्रधानमंत्री ली की यात्रा एक नए जोश-खरोश से भरी होनी चाहिए जिससे दोनों के द्विपक्षीय सहयोग और मित्रतापूर्ण सम्बंधों में बढ़ोतरी हो सके। बेहतर होगा कि भारत और चीन के युवाओं का एक-दूसरे देश में आना-जाना हो, सीमा विवाद का समाधान हो, साथ ही सीमा पर बने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध निर्माण जैसे मुद्दों का भी हल निकले, चीन की पाकिस्तान को दी जा रही सैन्य सहायता बंद हो और भारत-चीन

के बीच व्यापार असंतुलन में सुधार हो। ''भाजपा का यह भी कहना है कि दोनों देशों के बीच विश्वास स्तर भी सुधरे ताकि दोनों देश लम्बे समय तक दोस्त बने रहें। मजबूत चीन-भारत सम्बन्धों के लिए चीन को इन मुद्दों की संवेदनशीलता को समझना चाहिए और उसे इन पर अधिक गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

'ग्लोबल टाइम्स' जैसे चीनी मीडिया ने अपने सम्पादकीय प्रकाशित कर कहा है कि ''चीन-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धों में कई कमजोरियां है जिनका दूसरे बाहरी देश लाभ उठा सकते हैं। पारस्परिक सम्मानभाव रखे बिना छोटे-छोटे विवाद भी बड़े बन सकते हैं, स्पष्ट ही उसका इशारा भारत क्षेत्र में चीनी फौजों के 19 कि.मी. तक घुसपैठ करने के बाद लद्दाख क्षेत्र में डीओबी के सैन्य गतिरोध के बारे में था।

समाचार-पत्र का यह भी कहना है कि ''चीन के आस-पास के वातावरण को गहरा धक्का लगेगा यदि भारत, जो इस समय चीन के साथ कदम-कदम मिलाकर चल रहा है, कहीं चीन की नीतियों के कारण एक और जापान या फिलीपींस न बन जाए।''

यदि चीन अपने सबसे बड़े पड़ोसी देश के साथ अच्छे द्विपक्षीय सम्बंध चाहता है तो चीन के प्रधानमंत्री को स्वयं अपने मीडिया की आवाज को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसे उत्तरदायी रूप से व्यवहार करना चाहिए तथा भारत के साथ लम्बे समय से चले आ रहे सीमा-विवाद का समाधान करने के लिए तंत्र-सुधार कर अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए।

नि:संदेह, आज यह परम आवश्यक है और यह दोनों देशों के हित में भी है तथा चीन और भारत के लोग शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं, जिससे एशिया और पूरे विश्व के लिए यह स्थिति वरदान बन सकेगी। इसके बाद ही विश्वास की कमी सहयोग में परिवर्तित होगी, दोनों देशों के बाजार एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं, दोनों प्रमुख विकसित अर्थ व्यवस्थाएं समान विकास की राह पर चल सकती हैं और दोनों पड़ोसी देश पारस्परिक हित और समृद्धि के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।■

मध्य प्रदेश

सरकार की योजनाओं की जानकारी नीचे तक पहुंचाने की जरूरत

गत 16 मई को भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों, जिलाध्यक्षों, महामंत्रियों और संगठन मंत्रियों की बैठक यह रेखांकित किया गया कि सरकार की योजनाओं की जानकारी नीचे तक पहुंचाने की जरूरत है। खासकर, अन्नपूर्णा योजना के बारे में लोगों को बताया जाय। विदित हो कि अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीबों को एक रुपए किलो गेहूं, दो रुपए किलो चावल और एक रुपए किलो नमक देने का प्रावधान है। सरकार जगह-जगह अन्नपूर्णा मेले लगाएगी और भाजपा कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचे।

बैठक में राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार ने कहा कि प्रदेश में सत्ता विरोधी माहौल नहीं है, चुनाव जीतने जिला और मंडल स्तर पर एकता और सक्रियता की जरूरत है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस से डरो मत और अतिविश्वास से बचो। मैं भी घर नहीं बैठता आप भी मत बैठो। श्री चौहान ने कहा कि जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति और सरकार की योजनाओं की जानकारी नीचे तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने 24 घंटे बिजली तथा अन्य योजनाओं का जिक्र किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही भाजपा सत्ता में है और आगे भी बनी रहेगी। अन्नपूर्णा योजना तीन जून से लागू होगी, इसे उत्सव की तरह मनाना है। इसके अलावा बैठक में 31 मई को ग्वालियर में आयोजित हो रहे नगर और ग्राम केंद्रों के पालक संयोजकों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल ने कहा कि विधायक और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की सुनें, उन्हें साथ लेकर ही चुनाव में प्रभावी जीत हासिल की जा सकती है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जोर शोर से जनता को बताएं। पार्टी महासचिव श्री अनंत कुमार ने बैठक का समापन करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री चौहान की लोकप्रियता हमारी ताकत है और सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। चुनाव में केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफ विपक्ष के नेता भी करते हैं। चुनाव जीतने के लिए क्रिकेट मैच की तरह तैयारी करनी होगी, हर खिलाड़ी जीत के लिए खेले। बूथ लेवल एजेंट नियुक्ति पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए। हर बूथ पर वोट जुड़ने और कटने से चुनाव का नतीजा बदल जाता है। ■

संवाद और समन्वय से चलता है गठबंधन : मंगल पाण्डे

भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री मंगल पांडे ऊर्जावान युवा नेता एवं कुशल संगठक के तौर पर जाने जाते हैं। प्रदेश भाजयुमो के अध्यक्ष रह चुके व वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य श्री पांडे का मानना है कि राजग सरकार की सभी विकासात्मक गतिविधियों के मूल में अंत्योदय की नीति है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि गठबंधन संबंध, संवाद और समन्वय से चलता है। गत 17 मई 2013 को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में श्री पांडे से विकास आनंद ने कई मुद्दों पर बातचीत की। प्रस्तुत है प्रमुख अंश:-

इस समय भाजपा-जद(यू) गठबंधन की स्थिति से आप संतुष्ट हैं?

गठबंधन ठीक से चल रहा है और हम चाहते हैं कि गठबंधन मजबूत बना रहे। लेकिन गठबंधन वीटो या दबाव से नहीं चलता। गठबंधन संबंध, संवाद और समन्वय से चलता है। इसका ध्यान गठबंधन में रहने वाले दलों को रखना चाहिए।

आप अब तक के बिहार भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष हैं? युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं?

इस देश का इतिहास रहा है हमेशा युवाओं ने इस देश को दिशा दी है चाहे वह स्वामी विवेकानन्द हों, सरदार भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद हों या आज साइरस मिस्त्री हों। राजनीति में भी स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद हमेशा सार्थक उद्देश्य के लिए युवाओं ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की है। आज भी बिहार में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है चूंकि आज बिहार को भी विकास के विभिन्न आयामों में आगे बढ़ना है। चाहे उद्योग, व्यापार या अन्य आर्थिक उन्नयन शिक्षा तकनीक हो या राजनीति हो युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिहार भाजपा राज्य के 65 प्रतिशत युवा आबादी को अपने साथ जोड़कर सुशासन के माध्यम से राज्य को विकसित राज्य बनाना चाहती है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी महिलाओं की है। और महिलाएं बड़ी सहभागिता को इसके लिए पार्टी प्रयासरत है।

आप भाजपा संगठन को सशक्त और सुदृढ़ करने के लिए क्या योजना बनाई है?

भारतीय जनता पार्टी राज्य के 56 हजार बूथों पर बूथ समिति बनाने का काम कर रही है। सभी मोर्चे और मंचों की संरचना प्रखंड और पंचायत स्तर पर खड़ी हो जाए और उनके कार्यक्रम और गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हों इसे सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। केन्द्र सरकार की गलत नीतियां खासकर महंगाई, भ्रष्टाचार कालाधन राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा जैसे मुद्दे पर केन्द्र की सरकार नकाम रही है। इन सारे मुद्दे को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक ले जाना और भाजपा नीत राजग गठबंधन के पक्ष में लोगों को गोलबंद करना ताकि हम आगामी लोकसभा चुनाव में कार्यक्रम के माध्मय से यूपीए सरकार को अपदस्थ करने में बिहार की बड़ी भूमिका तय कर सकें और 40 लोकसभा सीट पर एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीत सकें इस तैयारी में लगे हैं।

भाजपा आज के परिवेश में कितनी संगठित और एकजुट है?

भाजपा बिहार में पूर्ण रूप में संगठित और एकजुट है। एकता और सक्रियता के मंत्र साथ राज्य के आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी लगी है।

पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा और जनता दल(यू) में सीटों के बंटवारे का जो फार्मूला था अभी भी वही रहेगा या परिवर्तन की संभावना है?

चुनाव आने के समय इस पर विचार करेंगे।

बिहार चुनाव में जातीय समीकरण बहुत प्रभावित करता है, इस पर आप क्या कहेंगे?

आज राज्य की जनता जातीय गोलबंदी से ऊपर उठकर बिहार के विकास के मामले के साथ गोलबंद हुई है। और हमलोग सरकार में रहते हुए सभी जाति, धर्म, सम्प्रदाय की चिंता की है। इस लिए आज हमारे साथ सभी धर्म सम्प्रदाय के लोग हैं और चुनाव के समय वर्ग सम्प्रदाय नहीं बल्कि बिहार का विकास और केन्द्र का नेतृत्व मुद्दा होगा।

दो दिन पहले पटना में लालू यादव की परिवर्तन रैली हुई। उस दिन काफी आम जनता को परेशानी हुई। क्या आपको नहीं लगता कि कॉलेज, विश्वविद्यालय में जाकर, प्रखण्ड, जिला स्तर पर कार्यक्रमों, छोटी सभा द्वारा जनता से सीधा संवाद करना चाहिए?

जहां तक परिवर्तन रैली की बात है यह पूर्ण रूप से मुद्दा विहीन रैली थी। महंगाई, भ्रष्टाचार, घपले और घोटाले में केन्द्रीय मंत्री का जेल जाना बिहार के साथ केन्द्र का भेदभाव इन मुद्दों की रैली में कोई चर्चा नहीं हुई। राजद ने इस रैली में नहीं बताया कि वह कैसा और किस तरह से परिवर्तन करना चाहता है। ऐसा लगा कि राजद में नेतृत्व परिवर्तन की रैली है। इस रैली के माध्यम से लालू जी ने अपने बेटे को नेतृत्व देने का प्रयास किया। राज्य के अंदर विभिन्न स्थानों पर जाकर राजद के नेता को राज्य और राष्ट्र की स्थितियों पर चर्चा करना ज्यादा बेहतर होता। इतनी बड़ी भीड़ बुलाकर साधन का अपव्यय करना जिसमें कोई सार्थक मुद्दा न हो, धन का अपव्यय है।

विशेष राज्य के बारे में आपकी क्या राय है। बिहार को यह क्यों मिलना चाहिए?

बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार में प्रति व्यक्ति औसत आय कम है। राज्य की आधारभूत संरचनाएं अविकसित हैं। बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं से राज्य प्रभावित रहता है। राज्य की बड़ी सीमा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है, जहां विकास की और आवश्यकता है। उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े हैं इसलिए राज्य को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए ताकि केन्द्र सरकार करों के मामले में रियायत और केन्द्रीय सहायता अधिक मिल सके।

ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के मंत्री काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उस हिसाब से इस गठबंधन सरकार में उन्हें महत्व नहीं मिल रहा है?

ये गठबंधन की सरकार है। और सम्पूर्ण सरकार के कार्यो में भाजपा की भागीदारी है। और राज्य की सरकार जितने विकास के कार्य कर रहे हैं उन सभी विकासात्मक कार्यो में नीतियां हैं अन्त्योदय, सुशासन विकास के मूल में है। सम्पूर्ण विकास में जो वित्तीय प्रबंधन है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान इस राज्य के वित्त मंत्री श्री सुशील मोदी जी का है।

भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी भाजपा का राष्ट्रीय वोट प्रतिशत 10 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखे थे। बिहार भाजपा इसके लिए क्या कदम उठा रही है?

भाजपा लगातार संगठन का विस्तार सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से कर रही है। इसके कारण हम इस योजना में सफल होंगे। ■

पृष्ठ 17 का शेष

36	आर्थिक गतिविधियां	श्री सी. राजशेखर	श्री आमोद अग्रवाल
37	शिक्षक	नरेन्द्र सिंह	प्रो. रघुवीर नंदन
38	सुशासन **प्रभारी**- विनय सहस्रबुद्ध	श्री राम नाईक	श्री नितिन पटेल श्री जोसफ अल्फोंसे सुश्री शिखा त्यागी श्री एस.के. सिंह
39	गंगा समग्र **प्रभारी**- सुश्री उमा भारती	अनिता सिंह	आचार्य हरिओम
40	सुरक्षा **प्रभारी**- ज. एन.एस. मलिक	श्री पी. चन्द्रशेखर	श्री सुभाष चौहान

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 8-9 जून को गोवा में

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो-दिवसीय बैठक 8-9 जून को गोवा में आयोजित की जाएगी तथा इससे पूर्व 7 जून को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की हर मार्चे पर विफलताओं के खिलाफ जन जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन तथा आगामी विभिन्न चुनावों के लिए संगठन को पूरी तरह तैयार करने का एक ब्लू-प्रिंट बनाना, गोवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेण्डे पर सर्वोच्च स्थान पर रहेगा। ■

गुजरात से आगे निकलेगा छत्तीसगढ़ : नरेन्द्र मोदी

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है, जो अपने पांच साल के काम-काज का हिसाब कड़ी धूप और तेज गर्मी में भी गांव-गांव जाकर जनता को दे रहे हैं। श्री मोदी ने डॉ. रमन सिंह को मुख्यमंत्री के पद से ज्यादा जनता के दिलों पर राज करने वाला लोकप्रिय, तेजस्वी और ऊर्जावान नेता बताया। श्री मोदी ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि नया राज्य होने के बावजूद यह विकास के मामले में अगले पांच साल में गुजरात से भी आगे निकल जाएगा।

श्री नरेन्द्र मोदी जिला मुख्यालय राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ सरकार की विकास यात्रा के कार्यक्रम के तहत एक विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। लगभग एक लाख लोगों के उमड़ते जनसैलाब को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के तीव्र विकास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इक्कीसवीं सदी के भारत की तमाम समस्याओं के इलाज के लिए दो ही प्रमुख जड़ी-बूटियां हैं और वे हैं विकास और भरोसा। उन्होंने कहा कि जनता की बेहतरी के लिए देश के लोकतंत्र में आज विकास की राजनीति सबसे ज्यादा जरूरी हो गयी है। छत्तीसगढ़ के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। यहां के मुख्यमंत्री बड़ी कुशलता और विनम्रता के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं। उनकी वाणी में मुझे कभी कटुता कभी नहीं दिखी। उनके विगत पांच साल की तुलना में वर्तमान पांच साल के कार्यकाल में विकास के सैकड़ों गुना यादा काम हुए हैं और हो रहे हैं। यह देखकर मुझे गर्व होता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे गर्व है कि डॉ. रमन सिंह मेरे मित्र हैं।

विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ : लालकृष्ण आडवाणी

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष व पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने 6 मई को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में होने वाली विकास यात्रा का शुभारंभ किया। छह हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी यह विकास यात्रा 20 जून तक चलेगी। श्री आडवाणी ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता के मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ छह हजार एक सौ किलोमीटर की प्रदेशव्यापी विकास यात्रा का शुभारंभ किया। श्री आडवाणी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री आडवाणी ने आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश और समाज में जन-जागरण की ष्टि से यात्राओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आदिवासी बहुल नए छत्तीसगढ़ राज्य में विकास यात्राओं का आयोजन वास्तव में गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह देखकर बहुत खुशी होती है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ ने विगत एक दशक में आम जनता और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्ग की बेहतरी को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनके लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। ■

श्री मोदी ने विशाल जनसभा में अपने ओजस्वी उदबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने विकास के साथ विश्वास यानी भरोसे का एक नया उदाहरण पेश किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहे विकास की चर्चा करते हुए यह भी विश्वास जताया कि अगले पांच साल में विकास के मामले में छत्तीसगढ़ गुजरात से भी आगे निकल जाएगा और इस पर हमें गर्व होगा। उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि देश का हर राज्य छत्तीसगढ़ की तरह तेज गति से तरक्की करे और गुजरात से आगे निकल जाए। ऐसा होगा तो हमें सबसे यादा खुशी होगी। श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि नया राज्य होने के बावजूद यहां कृषि उत्पादन और सिंचाई का रकबा बढ़ा है। राज्य का बजट छह हजार करोड़ से बढ़कर 44 हजार करोड़ रूपए तक पंहुच गया है। प्रति व्यक्ति आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है। सामान्य लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जब सामान्य जनता की क्रय शक्ति बढ़ती है तो बाजार में भी तेजी आती है। यह नया राज्य हर क्षेत्र में तरक्की के परचम लहरा रहा है। यह केवल विकास के एजेण्डे, जनता की मेहनत और सरकार के बेहतर प्रबंधन से ही संभव हुआ है। राजनीतिक स्थिरता की ताकत को छत्तीसगढ़ की जनता ने पहचाना है। हर गरीब को भोजन, हर बीमार को इलाज, हर खेत को पानी, हर पशु को चारा यह विकास का मूलमंत्र है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ ने देश का पहला बिजली कटौती मुक्त राज्य होने का गौरव हासिल किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य की दो करोड़ 55 लाख जनता की ओर से श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से मोदी का नाता बहुत पुराना है। वे पहले भी यहां आते रहे हैं। इसलिए उन्हें यहां के हर इलाके बारे में अच्छी जानकारी है। श्री मोदी ने गुजरात को देश का विकसित राज्य बनाकर भारत को विकास का एक नया मॉडल दिया है।

डॉ. रमन सिंह ने इस महीने की छह तारीख से प्रारंभ प्रदेश व्यापी विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि 45 डिग्री तापमान की तेज धूप में भी हजारों-लाखों लोग इस यात्रा में उत्साह के साथ भागीदार बन रहे हैं। दन्तेवाड़ा से प्रारंभ 6100 किलोमीटर की इस यात्रा के दो चरणों में अब तक लाखों लोगों से मिलने का अवसर मिल चुका है। यात्रा के रास्ते में जब 70-80 वर्ष की वृद्ध माताएं भी अपने दोनों हाथों से हमारे काफिले को आशीर्वाद देती नजर आती हैं तो लगता है कि मुख्यमंत्री के नाते मैंने जनता की सेवा के लिए जो कुछ भी किया है, उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आम सभाओं और स्वागत सभाओं में जगह-जगह विशाल जनसैलाब उमड़ता है।

विकास यात्रा के राजनांदगांव प्रवेश पर रात चार घण्टे तक पूरा शहर यहां की सड़कों पर उमड़ता रहा। राजनांदगांव के लोगों ने ऐसा स्वागत किया कि उनका बेटा कोई बड़ा काम करके घर आया है। डॉ. रमन सिंह ने जनता से कहा कि मैं आप सबकी वजह से मुख्यमंत्री हूं, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद और आपका विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है।

जनसभा में प्रदेश के वाणिय और उद्योग मंत्री राजेश मूणत और लोकसभा सांसद मधुसूदन यादव सहित जिले के अनेक जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। ■

केरल

खाद्य बिल पर घड़ियाली आंसू बहा रही है कांग्रेस

खाद्य सुरक्षा विधेयक के मार्ग में अवरोध पैदा करने को लेकर विपक्ष पर गरीबों के खिलाफ काम करने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कहा कि सत्तारूढ पार्टी 'घड़ियाली आंसू बहा रही है' जबकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी है।

गत 20 मई को तिरुवनंतपुरम में भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा, ''कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है और विपक्ष द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ भी जवाब नहीं दे रही है।'' श्रीमती सीतारमण ने आश्चर्य जाहिर किया कि क्यों कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कभी भी कांग्रेस शासित आंध्रप्रदेश का दौरा नहीं किया, जहां तीन मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर इस्तीफा दिया और उच्चतम न्यायालय ने छह अन्य मंत्रियों के खिलाफ नोटिस जारी किया था।

संसद को बाधित करने के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस की मानसिकता विपक्षियों से दुश्मन की तरह व्यवहार करने जैसा है।' ■

प्रादेशिक समाचार

झारखंड

यूपीए अब तक की भ्रष्टतम सरकार : राजनाथ सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने यूपीए को अब तक की भ्रष्टतम सरकार करार दिया है। उन्होंने बढ़ती महंगाई का दोष भी कांग्रेस की गलत नीतियों पर मढ़ा। गत 20 मई को रांची आए श्री सिंह ने पत्रकारों से कहा कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर खतरे भी मंडरा रहे हैं, जिनके लिए यूपीए सरकार ही दोषी है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल है। आने वाले चुनावों में केंद्र और झारखंड दोनों जगहों पर भाजपा नेतृत्व की सरकार बनेगी।

बेलगाम महंगाई को लेकर यूपीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लगातार बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ने का कोई अंतरराष्ट्रीय कारण नहीं है। यह सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और भ्रष्टाचार का नतीजा है। वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा और चालू वित्तीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यह सरप्लस था। उस समय अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की साख बढ़ रही थी लेकिन इस सरकार में लगातार गिर रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। मनमोहन कैबिनेट के मंत्रियों को जेल जाना पड़ रहा है और त्यागपत्र देना पड़ रहा है। भाजपा ने सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा कर सरकार को ऐसा करने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के सारे मामलों पर तो चर्चा नहीं करुंगा पर इतना अवश्य कहूंगा कि इस सरकार में 5.50 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। यदि यह धनराशि गरीब, किसान और जवानों पर खर्च की जाती तो देश का बहुत कल्याण हो सकता था। हमने भी छह साल सरकार चलाई थी लेकिन किसी भी मंत्री पर एक उंगली तक नहीं उठी। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का मामला भी उठाया। कहा, इस सरकार में संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोलगेट मामले में सीबीआइ रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई। भाजपा ने इन सभी मुद्दों को लेकर 27 मई से दो जून तक पूरे देश में जेल भरो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। संसद में प्रभावी लड़ाई लड़ने के बाद भाजपा अब भारत को संकट से निकालने के लिए सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेगी। श्री सिंह ने रोजगार सृजन की चर्चा करते हुए कहा कि 1998 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 6.70 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था, जबकि 2004-10 के बीच यूपीए सरकार के दो कार्यकाल में महज 27 लाख लोगों को रोजगार मिल सका। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब इस सरकार को जाना ही होगा। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कानून मंत्री का इस्तीफा प्रधानमंत्री को बचाने के लिए लिया गया लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा।

भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने झारखंड में भाजपा नेतृत्व की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा को भंग कर नए जनादेश के लिए अविलंब चुनाव होने चाहिए। इस राज्य में भाजपा ही स्थायी सरकार दे सकती है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रवींद्र राय, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व उपमुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे।■

बिहार

भाजपा ने यूपीए सरकार को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा

भारतीय जनता पार्टी, बिहार प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने 4 मई को राजभवन मार्च किया और राज्यपाल डी. वाई. पाटिल से मुलाकात कर कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग की और इस मामले में एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री मंगल पांडेय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल पाटिल से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन घोटाला सहित अनेक मामलों का उल्लेख किया गया है। ज्ञापन में इन घोटालों के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री को पी. चिदंबरम को जिम्मेवार ठहराया गया है तथा सरकार को तुरंत हटाने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

इस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री

जगत प्रकाश नड्डा, उपाध्यक्ष सी. पी. ठाकुर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय सहित कई नेता शामिल थे।■

हिमाचल प्रदेश

यूपीए ने किया संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्य सभा सदस्य श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन व संवैधानिक संस्थाओं से खिलवाड़ के खिलाफ भाजपा ने देशव्यापी अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत पूर देश में भाजपा 27 मई से 2 जून तक जेल भरो आंदोलन चलाएगी। यह आंदोलन ऐतिहासिक होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिल्ली में सभी प्रदेशों के पार्टी अध्यक्षों, संगठन मंत्रियों के साथ बैठकर विस्तृत योजना तैयार की गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी पूरी ताकत लगा देगी।

गत 19 मई को मंडी में श्री नड्डा ने कहा कि संसद क्यों नहीं चल पाई इसकी जिम्मेवार कौन है यह सच्चाई जनता तक पहुंचाई जाएगी। कानून मंत्री व रेल मंत्री से भाजपा इस्तीफा मांग रही थी और इसी कारण से संसद चल नहीं पा रही थी।

भाजपा का आंदोलन सही था और संसद सत्र खत्म होने के बाद जिस तरह से दोनों मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया यह इस बात का प्रमाण है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। इस सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया है, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की बात करती हैं मगर जब इस बार में संसद में आवाज उठाई जाती है तो आर पार की लड़ाई की बात की जाती है, बाद में समझौता कर लिया जाता है।

इस मौका पर उनके साथ मंडी सुंदरनगर के जिलाध्यक्ष सर्व श्री अध्यक्ष जवाहर ठाकुर व राकेश जमवाल, पूर्व मंत्री व विधायक जय राम ठाकुर व महेंद्र सिंह, विधायक कर्नल इंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष राम स्वरूप समेत बड़ी तादाद में वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

श्री नड्डा इससे पहले सुंदरनगर व मंडी में कार्यकर्ताओं की भी बैठक को संबोधित किया तथा उन्हें चुनाव के लिए कमर कसने के लिए कहा।■

उत्तर प्रदेश

कांट्रेक्ट फार्मिंग लागू न होने देगी भाजपा

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने 21 मई को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर सपा सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए बर्खास्त करने की मांग का ज्ञापन राज्यपाल को भेजा। प्रदेश मुख्यालय में प्रदर्शन का नेतृत्व किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री विजयपाल सिंह तोमर ने किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उपाध्यक्ष श्री राजवीर सिंह राजू भैया, श्री लाल जी टंडन एवं मंत्री श्री अश्विनी त्यागी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

डॉ. वाजपेयी ने कहा कि मात्र सवा साल के शासनकाल में समाजवादी पार्टी का किसान विरोधी चरित्र उजागर हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे किसानों को बर्बाद करने वाले फैसलों के बाद सपा प्रमुख मुलायम सिंह को भी खुद को धरतीपुत्र कहलाने का हक नहीं रह गया। उन्होंने नई कृषि नीति में कांट्रेक्ट फॉर्मिंग जैसे घातक फैसले शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भर्त्सना की और किसान विरोधी प्रावधान लागू न होने देने का एलान किया। किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री विजयपाल तोमर ने छह हजार करोड़ रुपये बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न होने, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व पानी उपलब्ध न हो पाने व गेहूं खरीद में अनियमितता बढ़ने का आरोप लगाते हुए आरपार के संघर्ष का एलान किया।

भाजपा कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए पार्टी मुख्यालय से पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए निकले लेकिन पुलिस ने हजरतगंज चौक से आगे नहीं जाने दिया तो राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन एसीएम को सौपा गया। राजधानी लखनऊ सहित सहारनपुर, नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर, मेरठ, मऊ, मुजफरनगर, बिजनौर, अलीगढ़ व मुरादाबाद समेत सभी जिलों में सफल प्रदर्शन हुए। ■

उत्तराखंड

जनता का हक छीन रही सरकार

एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए चावल के कोटे में कटौती व मूल्य वृद्धि किए जाने के मामले में विपक्षी दल

भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता को सहूलियतें देने में तो पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है, उल्टा पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में दी गई सुविधाओं पर भी बेरहमी से कैंची चला रही है। आम जनता आगामी चुनावों में भी कांग्रेस को इन जनविरोधी नीतियों का माकूल जवाब देगी।

एपीएल श्रेणी के लिए चावल का कोटा कम करने व मूल्य बढ़ाने संबंधी कैबिनेट के निर्णय को नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गत 22 मई को जागरण से फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि यह निर्णय कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों का एक और उदाहरण है। पिछली भाजपा सरकार ने एपीएल उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर दस किलोग्राम चावल देने की योजना शुरू की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही जनता के इस हक पर डाका डालना शुरू कर दिया।

कांग्रेस सरकार जनता को सहूलियतें देने की बजाय छीन रही है, जबकि अपने फालतू खर्चों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर हड़ताल पर बैठे टीइटी प्रशिक्षुओं को जल्द मौलिक नियुक्ति दिलाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि 13 मई से हड़ताल पर बैठे टीइटी प्रशिक्षुओं की सरकार ने अब तक सुध नहीं ली है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में महाधिवक्ता को न्यायालय में उचित पैरवी के लिए आदेश देने की मांग की। साथ ही, कोर्ट में पैरवी न होने पर आगामी विधानसभा सत्र में यह मामला उठाने की चेतावनी भी दी।■

राजस्थान

सड़क पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट मे राजस्थान में विपक्ष के नेता और पूर्व गृहमंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया को आरोपी बनाए जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सीबीआई की इस कार्रवाई के विरोध में भाजपा के आह्वान पर 19 मई को आयोजित राजस्थान बंद का व्यापक असर रहा। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में उर्स के कारण अजमेर को बंद से मुक्त रखा गया था। जयपुर में बंद समर्थकों की अगुवाई जहां पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे एवं राष्ट्रीय सचिव श्री भूपेन्द्र यादव ने की, वहीं कटारिया के गृह नगर उदयपुर में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती किरण माहेश्वरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी सड़कों पर उतरे। श्री कटारिया के समर्थन में भाजपा के साथ एकजुट हुए एक सौ सत्ताईस संगठनों ने राजस्थान बंद का आगाज किया। बंद से राज्य का व्यापार और उद्योग काफी प्रभावित रहा।

बंद के कारण प्रदेश के प्रमुख बाजारों में व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खुले। अस्पताल, यातायात जैसी आवश्यक सेवाओं का बंद से मुक्त रखा गया था।

भाजपा कार्यकर्ताओं कार्यकर्ता दुकानदारों से बंद को समर्थन की अपील करते देखे गए। जयपुर में श्रीमती वसुंधरा राजे ने एक साइकिल रिक्शे में बैठकर लोगों से दुकानें बंद करने की अपील की,यहां सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती वसुंधरा राजे ने सीबीआई को खिलौने की संज्ञा दे दी। श्रीमती राजे ने कहा कि सीबीआई केन्द्र के उस खिलौने जैसी है, जिसमें जैसी चाबी भरो वह वैसा ही बोलता है।

उन्होंने कहा कि अब राजस्थान में भी सरकार सीबीआई को पैसे खिलाने की तरह काम में ले रही है। प्रदेश के सीकर, बीकानेर, सवाई मोधापुर, कोटा, भरतपुर, चूरू, भीलवाड़ा, दौसा, झालावाड़, बांरा जिलों में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। इन जिलों में तो यातायात के साधन भी बहुत कम चले, तथा बंद को भारी समर्थन मिला। ■

भाजयुमो ने प्रधानमंत्री के खिलाफ किया उग्र प्रदर्शन

भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौजवानों ने 12 मई 2013 को प्रात:काल औरंगजेब रोड पर एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मनमोहन सरकार मुर्दाबाद के नारे, प्रधानमंत्री शर्म करो, देश पर रहम करो जैसे नारे लिखे हुए होर्डिंग, बैनर्स व पट्टिकाएं हाथ में लिए हुए जहां एक ओर मनमोहन सिंह की शव यात्रा निकाली वहीं दूसरी ओर यूपीए सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों को जेल में बंद दिखाया, साथ ही पवन बंसल एवं अश्विनी कुमार को बकरे के रूप में उनके ऊपर यह लिखा हुआ दिखाया कि मुझे बलि का बकरा न बनाओ बल्कि सही दोषी को सामने लाओ।

श्री ठाकुर ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज बार-बार युवा मोर्चा को सड़कों पर उतरने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ रहा है। सरकार के एक-एक करके लगभग सभी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं और सोनिया गांधी धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांधे हुए यह सब होता हुआ देख रही हैं। इन मंत्रियों के एक-एक करके सिर को कलम करने से कुछ नहीं होता क्योंकि इस भ्रष्टाचार रूपी रावण की नाभि में मनमोहन सिंह जैसा दोषी प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। जब तक उस नाभि पर प्रहार नहीं किया जायेगा तब तक भ्रष्टाचार का विनाश नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री के पास स्वयं की कोई नैतिकता शेष नहीं रह गई है। अत: युवा मोर्चा संघर्ष करेगा एवं देश भर में नौजवानों को जागरूक करेगा।

श्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि लगता है कि प्रधानमंत्री को लूट के लिए 10 जनपथ ने 10 साल का ठेका दे दिया है क्योकि कानून मंत्री व रेल मंत्री दोनों प्रधानमंत्री के लिए काम करते थे और उन्हें सारे भ्रष्टाचारों की जानकारी थी। फिर भी वह धृतराष्ट्र की तरह यह भ्रष्टाचार होता देखते रहे। आज जिस तरह से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार पर टिप्पणी की जा रही है इससे तो अच्छा है कि यह स्वयं शर्म से सत्ता से हट जाते, लेकिन बेशर्म हो चुकी यूपीए सरकार अपने अंतिम वक्त तक कुर्सी से चिपकी रहना चाहती है किन्तु युवा मोर्चा में आप जैसे संघर्षशील युवाओं के रहते यह हम किसी कीमत पर देश का चीर हरण होने नहीं देंगे चाहे इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस की एक न चली और उनके द्वारा लगाए गए बेरिकेड्स को जहां युवा मोर्चा के प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने वाटर केनन छोड़कर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस श्री अनुराग ठाकुर समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाना ले गई। ■

श्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौजवानों ने 12 मई 2013 को प्रात:काल औरंगजेब रोड पर एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मनमोहन सरकार मुर्दाबाद के नारे, प्रधानमंत्री शर्म करो, देश पर रहम करो जैसे नारे लिखे हुए होर्डिंग, बैनर्स व पट्टिकाएं हाथ में लिए हुए जहां एक ओर मनमोहन सिंह की शव यात्रा निकाली वहीं दूसरी ओर यूपीए सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों को जेल में बंद दिखाया।